अगस्त-सितम्बर, 2026, वर्ष-34, अंक-14

उत्तर प्रदेश

संदेश




"कानून-व्यवस्था में
सुधार का
सकारात्मक प्रभाव
महिलाओं पर पड़ा है।"
-योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
13%
36%
2017
महिला श्रम बल भागीदारी
2026
फैक्ट
check
विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार



उत्तर प्रदेश

संदेश

संरक्षक एवं मार्गदर्शक :

संजय प्रसाद

अपर मुख्य सचिव, सूचना

❖

प्रकाशक एवं स्वत्वाधिकारी :

विशाल सिंह

सूचना निदेशक

❖

सम्पादकीय परामर्श :

अरविन्द कुमार मिश्र

अपर निदेशक, सूचना

❖

चन्द्र विजय वर्मा

सहायक निदेशक (प्रकाशन)

❖

दिनेश कुमार गुप्ता

सूचना अधिकारी

❖

अजय कुमार द्विवेदी

सहयुक्त संपादक

सम्पादकीय संपर्क : सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पं. दीनदयाल उपाध्याय सूचना परिसर, पार्क रोड, लखनऊ

ईमेल : upsandesh20@gmail.com

दूरभाष कार्यालय : ई.पी.ए.बी.एक्स 0522-2239132-33, 9412674759, 7705800978

भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स की रजिस्ट्री संख्या - 55884/91

प्रकाशित सामग्री में विभिन्न लेखकों के दृष्टिकोण एवं विचार से सूचना विभाग की सहमति अनिवार्य नहीं है। लेखों में प्रयुक्त आंकड़े अनन्तिम हो सकते हैं।

इस अंक में

- उत्तर प्रदेश सड़क से समृद्धि तक — 3
  -विमल किशोर श्रीवास्तव
- युवाओं के समग्र विकास को सरकार प्रतिबद्ध — 8
  -प्रज्ञा पांडेय
- यूपी के विकास में जापान का साथ — 11
  -अनिल श्रीवास्तव
- कांवड़ यात्रा : आस्था, परंपरा और संस्कृति का संगम — 15
  -रुचि शिशिर मिश्रा
- उत्तर प्रदेश में एआई क्रांति — 18
  -डॉ. ऋतु दुबे तिवारी
- देश की रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाता यूपी — 21
  -सियाराम पांडेय 'शांत'
- महिला सुरक्षा और सम्मान पर जोर — 25
  -सुरेन्द्र अग्निहोत्री
- युवाओं का भविष्य और बदलते अवसर — 29
  -समर्थ आर्या
- उत्तर प्रदेश देश में नंबर-1 — 35
  -अजय मिश्रा
- आत्मनिर्भर युवा विकसित यूपी का मजबूत आधार — 38
  -आदर अदीब पावेल बन्धु
- मधु से मधुर होती जिन्दगी — 42
  -डॉ. सुयश नारायण मिश्रा
- बदलते युवाओं की तकदीर — 47
  -सुमन शेखर
- यूपी में सुशासन और विकास का नया अध्याय — 53
  -उपेन्द्र कुमार
- वृद्धाओं का सम्मान, सफर आसान — 56
  -कीर्ति श्रीवास्तव
- अटल आवासीय विद्यालय : वंचित बच्चों के सपनों को नई उड़ान — 60
  -सलोनी कसेरे

सम्पादकीय

उत्तर प्रदेश देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर न केवल अग्रसर है, बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश बनने की दिशा में भी सतत प्रयासरत है और इस निमित्त बेहद सधे कदम भी उठा रहा है। वर्ष 2017 में योगी सरकार बनने से आज तक सरकार ने एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया है। इसका असर राज्य की प्रगति और खुशहाली के रूप में दिख भी रहा है। चाहे ढांचागत विकास का मामला हो या फिर आम जन-जीवन में सुधार-परिष्कार का, विधि व्यवस्था के कील-कांटे दुरुस्त करने का मामला हो अथवा औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार देने का, योगी आदित्यनाथ सरकार हर कसौटी पर खरी उतरी है। केंद्र सरकार की एक भी ऐसी जनहितकारी योजना नहीं, जिसका उत्तर प्रदेश में बखूबी अनुपालन न हुआ हो। विधि व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार के उल्लेखनीय प्रयास देखते ही बनते हैं। हर सप्ताह नियमित राज्य मंत्रिमंडल की बैठकें इस बात का प्रमाण है कि सरकार के लिए प्रदेश की जनता के हित सर्वोपरि हैं। इसके लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। सत्ता की धाक का आलम यह है कि अपराधी और माफिया जेल में कैद रहने में खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार का हमेशा मानना रहा है कि इस प्रदेश के युवाओं को बेशक प्रगति की वैश्विक ऊँचाई तक जाना चाहिए, लेकिन अपनी जड़ों को भी हमेशा याद रखना चाहिए। नई पीढ़ी को ग्लोबल होना चाहिए क्योंकि यह मौजूदा दौर की जरूरत भी है लेकिन युवाओं को अपने हृदय में भारत को रखने का भी विचार करना चाहिए। सरकार सबका विकास चाहती है। इसमें शहर भी आते हैं और गांव भी आते हैं। शहर बहुत हद तक विकसित हैं लेकिन गांव उपेक्षित थे। सरकार ने गांवों की सुध ली है। किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं की सुध ली है। उनके सर्वांगीण विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। सरकार जानती है कि जब समाज और सरकार एक साथ चलती है तो विकास का पहिया अपनी पूरी गति से आगे बढ़ता है। सरकार और समाज की दिशा एक हो, संकल्प एक हो, लक्ष्य प्राप्ति के लिए दोनों साझा प्रयास करें तो अपेक्षा के अनुरूप परिणाम तो मिलते ही हैं।

स्वच्छता के मामले में तो उत्तर प्रदेश के शहरों की रैंकिंग बेहतर है ही, अब तो स्वच्छ हवा के मामले में भी उत्तरप्रदेश ने पूरे देश में अपनी सफलता का ध्वज लहरा दिया है। एक्सप्रेसवे निर्माण के मामले में भी उत्तर प्रदेश देश के किसी भी राज्य से आगे है। सड़क परिवहन हो, रेल परिवहन हो या फिर वायु परिवहन, उत्तर प्रदेश पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार जिस तरह विदेशी कम्पनियों को राज्य में निवेश के निमंत्रण दे रही है। उसके पीछे उसकी सोच हर हाथ को काम से जोड़ने की है। डिफेंस कॉरिडोर जिस तरह सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है, वहां उत्पादन शुरू हो रहा है, अनेक इकाइयों में शुरू भी हो गया है, वह एक अच्छी बात है। प्रदेश के लिए गौरव की बात है। शिक्षा व्यवस्था में उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर प्रदेश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल भी काबिलेगौर है। लखनऊ छावनी में हाल ही में 101 करोड़ की लागत वाली 12 परियोजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन यह बताता है कि उत्तर प्रदेश सरकार, रक्षा मंत्रालय और उद्योग जगत की युति राज्य में विकास कार्यों को निरन्तर गति प्रदान कर रही है। विकास और सुशासन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही है। विकास के साथ आस्था और विरासत का सम्मान भी यहां देखते ही बन रहा है। सितम्बर माह में प्रदेश भर में चल रही साहित्यिक गतिविधियां, पुरस्कार समारोह उत्तर प्रदेश की गौरव गरिमा में चार चांद लगा रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश जीवन के हर क्षेत्र में कुछ अलहदा और विशेष कर रहा है। इस विकास प्रवाह को आगे बढ़ाने में सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा सहयोगी सिद्ध हो रही है। प्रदेश में संघे शक्ति की भावना मूर्त रूप ले रही है। उम्मीद है, विकास की यह रफ्तार यथावत बनी रहेगी। यह अंक आप सुधी पाठकों को कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें सतत इंतजार रहेगा।

सम्पादक





उत्तर प्रदेश सड़क से समृद्धि तक

—विमल किशोर श्रीवास्तव

कभी उत्तर प्रदेश की पहचान खराब सड़कों, लंबे सफर, यातायात की कठिनाइयों और औद्योगिक पिछड़ेपन की चुनौतियों से जुड़ी हुई थी। आज वही उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े और तेजी से विकसित हो रहे एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाले राज्यों में अपनी अलग पहचान बना रहा है। यह बदलाव केवल सड़कों के निर्माण तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी विकास–दृष्टि दिखाई देती है, जिसमें बेहतर कनेक्टिविटी को निवेश, उद्योग, रोजगार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

यह परिवर्तन केवल सड़कों के निर्माण की कहानी नहीं है। बल्कि वर्तमान सरकार के विकास की नई सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय स्तर के बुनियादी ढांचा विकास के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश स्तर पर मजबूत प्रशासनिक नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में इस परिवर्तन को गति दी है। इसी समन्वित प्रयास को व्यापक रूप से 'डबल इंजन सरकार' की कार्यशैली के रूप में देखा जाता है।

पहले और अब–उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर

कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा में लंबा समय लगता था। औद्योगिक क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में देरी होती थी और प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी तथा बुंदेलखंड क्षेत्रों के बीच आर्थिक संपर्क अपेक्षाकृत कमजोर था। उत्तर प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्यों में है। पश्चिम में मेरठ और आगरा से लेकर पूर्व में गोरखपुर, वाराणसी और गाजीपुर तक तथा बुंदेलखंड के विस्तृत क्षेत्र तक फैले प्रदेश में बेहतर सड़क संपर्क हमेशा विकास की महत्वपूर्ण शर्त रहा है।



अतीत में लंबी दूरी के आवागमन में अधिक समय लगना, माल परिवहन की धीमी गति और अनेक क्षेत्रों में औद्योगिक कनेक्टिविटी की कमी विकास के सामने बड़ी चुनौतियां थीं।

आज तस्वीर काफी बदल चुकी है

यही अंतर बताता है कि एक्सप्रेसवे केवल 'सड़क परियोजना' नहीं, बल्कि 'विकास परियोजना' बन चुके हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश को अलग–अलग आर्थिक क्षेत्रों में जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

इस बदलाव को केवल 'सड़क निर्माण' कह देना शायद इसकी व्यापकता को कम करके आंकना होगा। क्योंकि अच्छी सड़क केवल यात्रा आसान नहीं करतीय वह बाजार, उद्योग और अवसर तक पहुंच भी आसान करती है।

1. लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेसवे : दो शहरों के बीच नई आर्थिक धुरी

राजधानी लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जाती रही है। लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेसवे इस आवश्यकता को पूरा करने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है।

लगभग 63 किलोमीटर लंबे इस 6–लेन एक्सप्रेसवे, जिसमें एलिवेटेड सेक्शन भी शामिल हैं, का उद्देश्य दोनों शहरों के बीच यात्रा को अधिक तेज, सुरक्षित और सुगम बनाना है।

इसका प्रभाव केवल समय की बचत तक सीमित नहीं है

लखनऊ प्रशासनिक, शैक्षिक और सेवा क्षेत्र का प्रमुख केंद्र है, जबकि कानपुर का औद्योगिक एवं विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है।

इन दोनों शहरों को बेहतर एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी मिलने का अर्थ है–

- श्रमिकों और दैनिक यात्रियों के लिए बेहतर आवागमन
- माल परिवहन में समय की बचत
- उद्योगों के लिए बेहतर लॉजिस्टिक सुविधा
- दोनों शहरों के बीच आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि
- नए निवेश के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा

अर्थात लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेसवे केवल दो शहरों की दूरी कम नहीं करता, बल्कि दो आर्थिक क्षमताओं को जोड़ता है।

2. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे : पूर्वी उत्तर प्रदेश को नई गति

पूर्वांचल लंबे समय तक विकास की मुख्यधारा से अपेक्षाकृत पीछे रहने वाले क्षेत्रों में गिना जाता रहा है।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने इस स्थिति को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजधानी लखनऊ को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला यह मार्ग केवल यात्रा को आसान नहीं बनाता, बल्कि इसके आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की संभावनाओं को भी बढ़ाता है।

इसके माध्यम से–

लखनऊ → बाराबंकी → अमेठी → सुल्तानपुर → अयोध्या क्षेत्र → आजमगढ़ → मऊ → गाजीपुर

जैसे क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क का लाभ मिलता है। यह इस सरकार की उस सोच का उदाहरण है जिसमें विकास को केवल बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय प्रदेश के अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

3. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे : पिछड़े क्षेत्र से औद्योगिक संभावना तक

बुंदेलखंड लंबे समय से पानी, रोजगार और औद्योगिक अवसरों की चुनौतियों से जूझता रहा है।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने इस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के प्रमुख आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस परियोजना का वास्तविक महत्व तब समझ में आता है जब इसे केवल सड़क के रूप में नहीं, बल्कि 'बुंदेलखंड के आर्थिक पुनरुत्थान की आधारभूत संरचना' के रूप में देखा जाए।

बेहतर कनेक्टिविटी से –

- उद्योगों की स्थापना की संभावनाएं बढ़ती हैं,
- कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना आसान होता है,
- पर्यटन को बढ़ावा मिलता है,
- लॉजिस्टिक्स की लागत और समय घट सकता है,
- स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

4. गंगा एक्सप्रेसवे : पश्चिम से पूर्व को जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना

मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में से एक है।

इसका महत्व इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यह प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसे केवल यातायात परियोजना के रूप में देखना इसके व्यापक प्रभाव को कम करके आंकना होगा।

इसके संभावित प्रभावों में शामिल हैं –

बेहतर कनेक्टिविटी → तेज परिवहन → बेहतर लॉजिस्टिक्स → निवेश की संभावना → औद्योगिक गतिविधि → रोजगार।

प्रयागराज जैसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र तक बेहतर पहुंच पर्यटन और बड़े आयोजनों के दौरान आवागमन को भी सुविधा प्रदान कर सकती है।

5. गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे : पूर्वांचल के अंतिम छोर तक बेहतर संपर्क

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का महत्व पूर्वी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विशेष है।

यह गोरखपुर क्षेत्र को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़कर पूर्वी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करता है।

इस प्रकार एक्सप्रेसवे का नेटवर्क धीरे–धीरे अलग–अलग परियोजनाओं का समूह न रहकर एक–दूसरे से जुड़े हुए आर्थिक कॉरिडोर का स्वरूप ग्रहण कर रहा है।

यही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वास्तविक शक्ति है।

योगी आदित्यनाथ की भूमिका : केवल निर्माण नहीं, 'कनेक्टिविटी गॉडल' की सोच

उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे विकास की चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका के बिना अधूरी है।

योगी सरकार के कार्यकाल में सड़क एवं एक्सप्रेसवे निर्माण को केवल लोक निर्माण विभाग की पारंपरिक परियोजना के रूप में देखने के बजाय इसे निवेश, उद्योग और रोजगार से जोड़ने वाली व्यापक रणनीति के रूप में आगे बढ़ाया गया है।

योगी आदित्यनाथ की भूमिका को मुख्यतः चार स्तरों पर देखा जा सकता है–

1. परियोजनाओं को प्राथमिकता देना

बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स को शासन की प्राथमिकताओं में ऊपर रखना।



2. **प्रशासनिक गति**

भूमि अधिग्रहण, विभागीय समन्वय और परियोजनाओं की निगरानी में प्रशासनिक स्तर पर तेजी लाने का प्रयास।

3. **एक्सप्रेसवे को उद्योग से जोड़ना**

सरकार का लक्ष्य केवल सड़क बनाना नहीं, बल्कि उसके आसपास औद्योगिक क्लस्टर, लॉजिस्टिक हब, वेयरहाउसिंग और निवेश के अवसर विकसित करना है।

4. **क्षेत्रीय संतुलन**

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आर्थिक ताकत के साथ पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों को भी बेहतर कनेक्टिविटी देकर विकास के अवसरों से जोड़ना।

यही दृष्टिकोण योगी सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को केवल 'सड़क निर्माण' से आगे ले जाकर 'आर्थिक कॉरिडोर निर्माण' की दिशा देता है। इस सोच का सार स्पष्ट है– एक्सप्रेसवे मंजिल नहीं, विकास तक पहुंचने का माध्यम है।

'डबल इंजन' मॉडल का तुलनात्मक पक्ष

उत्तर प्रदेश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय को भी महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए।

केंद्र सरकार की भूमिका–राष्ट्रीय राजमार्ग, वित्तीय एवं नीतिगत सहयोग, बड़े राष्ट्रीय कनेक्टिविटी विजन और अंतरराज्यीय संपर्क।

राज्य सरकार की भूमिका–भूमि, स्थानीय प्रशासन, कानून–व्यवस्था, परियोजना क्रियान्वयन में समन्वय तथा प्रदेश की औद्योगिक एवं निवेश नीति के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का तालमेल।

जब ये दोनों स्तर एक ही विकास लक्ष्य के साथ काम करते हैं तो बड़े प्रोजेक्ट्स को गति देने की संभावना बढ़ती

है। इसी समन्वय को राजनीतिक भाषा में 'डबल इंजन सरकार' कहा जाता है।

एक्सप्रेसवे का अगला चरण : सड़क से आर्थिक कॉरिडोर तक

उत्तर प्रदेश के लिए अगली चुनौती केवल नए एक्सप्रेसवे बनाना नहीं है, बल्कि इन एक्सप्रेसवे को आर्थिक विकास के इंजन में बदलना है।

इसके लिए आवश्यक है कि एक्सप्रेसवे के आसपास– औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक हब, वेयरहाउस, कृषि आधारित उद्योग, एमएसएमई क्लस्टर, पर्यटन केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं विनिर्माण इकाइयां तेजी से विकसित हों।

यदि सड़क के दोनों ओर आर्थिक गतिविधियां विकसित होती हैं, तो एक्सप्रेसवे की उपयोगिता कई गुना बढ़ सकती है।इसी दिशा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कार्य भी कर रही है

भविष्य की कनेक्टिविटी : उत्तर प्रदेश का अगला चरण

प्रस्तावित एवं विचाराधीन विभिन्न परियोजनाएं उत्तर प्रदेश को और व्यापक राष्ट्रीय कनेक्टिविटी नेटवर्क से जोड़ने की क्षमता रखती हैं।

गोरखपुर–सिलीगुड़ी जैसे प्रस्तावित कॉरिडोर पूर्वी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को राष्ट्रीय स्तर पर नई दिशा दे सकते हैं, जबकि अन्य प्रमुख कॉरिडोर राज्य के औद्योगिक एवं धार्मिक केंद्रों के बीच यात्रा को और सुगम बनाने की संभावना रखते हैं।

इसलिए आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश का लक्ष्य केवल 'सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य' बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि 'एक्सप्रेसवे आधारित औद्योगिक और लॉजिस्टिक अर्थव्यवस्था' का मजबूत केंद्र बनना चाहिए जो वर्तमान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से साकार हो रहा है।

कभी उत्तर प्रदेश की पहचान खराब सड़कों, लंबे सफर, यातायात की कठिनाइयों और औद्योगिक पिछड़ेपन की चुनौतियों से जुड़ी हुई थी। आज वही उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े और तेजी से विकसित हो रहे एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाले राज्यों में अपनी अलग पहचान बना रहा है। यह बदलाव केवल सड़कों के निर्माण तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी विकास–दृष्टि दिखाई देती है, जिसमें बेहतर कनेक्टिविटी को निवेश, उद्योग, रोजगार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

सड़कें बदली हैं, अब अर्थव्यवस्था भी बदल रही है

उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का विस्तार निश्चित रूप से प्रदेश के बदलते बुनियादी ढांचे की बड़ी तस्वीर प्रस्तुत करता है।

लेकिन इस परिवर्तन का वास्तविक मूल्य केवल किलोमीटर में नहीं मापा जाना चाहिए।

इसका मूल्यांकन इस आधार पर भी होना चाहिए कि–

- कितना समय बचा?
- कितनी लॉजिस्टिक लागत कम हुई?
- कितना निवेश आया?
- कितने उद्योग स्थापित हुए?
- कितने रोजगार बने?
- और कितने पिछड़े क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से जुड़े?

इसी दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से हम लगातार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जिससे उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे वास्तव में विकास के 'गेम चेंजर' सिद्ध होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में परियोजनाओं को गति देने वाले नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के सामने विकास का एक नया अवसर प्रस्तुत किया है।

आज की सड़क कल की अर्थव्यवस्था की नींव है। उत्तर प्रदेश में बन रहा एक्सप्रेसवे नेटवर्क इस बात का संकेत है कि प्रदेश अब केवल अपनी दूरी कम नहीं कर रहा–बल्कि वह विकास की मंजिल तक पहुंचने की अपनी गति भी बढ़ा रहा है।

'नए उत्तर प्रदेश' की पहचान अब केवल उसके आकार से नहीं, उसकी कनेक्टिविटी, निवेश क्षमता और विकास की गति से भी तय होगी। ◆

(लेखक सेवानिवृत पुलिस अधिकारी और स्वतंत्र लेखक हैं)
मो. : 9936411588

युवाओं के समग्र विकास को सरकार प्रतिबद्ध

—प्रज्ञा पांडेय



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं के समग्र विकास को लेकर हमेशा चिंतित रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने देश की नई पीढ़ी को नवाचार से जोड़ने, उनके लिए जल्द नई नीति लाने की जो घोषणा की, उसे कमोवेश इसी रूप में देखा–समझा जा सकता है। वैसे भी उन्होंने जब से यूपी की कमान संभाली है, युवा उनकी प्राथमिकता के केंद्र में रहे हैं। युवाओं को आगे बढ़ाने का एक भी अवसर उन्होंने अपने हाथ से जाने नहीं दिया है। वर्ष 2017 से आज तक के उनके हर बजट में युवाओं के लिए बहुत खास होता रहा है।

उन्हें पता है कि युवा देश का भविष्य हैं। विकास की दौड़ में उनका पिछड़ना देश का सदियों पीछे चला जाना है। जिस देश का युवा जागरूक व सशक्त होता है, उस देश को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। सरकार जानती है कि किशोर से युवा होती पीढ़ी अपने भीतर संभावनाओं का असीम आकाश समाहित किए हुए है। उसे सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की जरूरत है। इसके अभाव में वह भटक भी सकती है। वैसे भी देश में युवाओं को भटकाने–भड़काने के जो प्रयास हो रहे हैं, उसे देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार की इस पहल का औचित्य सहज ही समझ में आने वाला है। सरकार की कोई भी योजना हो, वह युवाओं के हितों से जुड़ती जरूर है। युवा गांव का हो या शहर का, उसके सपने एक जैसे होते हैं। सरकार इस बात को समझती भी है और इसे व्यावहारिक धरातल पर लाने का प्रयास भी करती है।

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना, प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, यूपी स्टार्ट अप संवाद और एक्सपो का आयोजन यह बताने और जताने के लिए काफी है कि सरकार युवाओं के हितों को लेकर कितनी गंभीर है। युवाओं के लिए नवाचार कोष बनाने से लेकर पीआरडी

जवानों का मानदेय बढ़ाने, उन्हें 20 लाख अतिरिक्त रोजगार दिवस उपलब्ध कराने, उन्हें निःशुल्क कैशलेस इलाज की व्यवस्था हेतु सरकार की प्रतिबद्धता यह बताती है कि युवाओं का सर्वांगीण विकास उसके लिए कितना अहम है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत विगत 6 साल में राज्य के 15 लाख 25 हजार युवाओं ने निःशुल्क रोजगारपरक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसमें से 5 लाख 71 हजार युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार से जोड़ने में सरकार को सफलता मिली है। सरकार की अप्रेंटिस योजना के तहत अब तक ढाई लाख से अधिक युवाओं को बड़े और लघु उद्योगों से जोड़ा गया है। सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों की संख्या बढ़कर 96 लाख हो गई है। उसमें एक करोड़ 65 लाख लोग काम कर रहे हैं जिनमें सर्वाधिक युवा हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो शिक्षा से लेकर रोजगार प्रदान करने तक सरकार युवाओं के हित संवर्धन को निरंतर आगे बढ़ा रही है। स्कूल–कॉलेजों की गुणवत्ता सुधारने के साथ ही, वह हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रही है।

उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसके पास खेल विश्वविद्यालय है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावास हैं। केंद्रीय खेल प्रशिक्षण शिविर की व्यवस्था है। स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी है। खेलो इंडिया ऐप है तो उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति भी है। एकलव्य क्रीड़ा कोष है तो खेल साथी ऐप और पोर्टल भी है। प्रदेश के 107 सरकारी और निजी विश्वविद्यालय हर क्षण युवाओं की प्रतिभा को धार देने का काम कर रहे हैं। मतलब जितना बड़ा यह प्रदेश है, उतना ही बड़ा इसका दिल भी है। अपने युवाओं को संवारने –निखारने का राज्य सरकार का संकल्प राज्य को उत्तम प्रदेश निर्माण के उच्च शिखर पर ले जाएगा, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। छात्रवृत्ति को ही लें तो उनके शासन में छात्रवृत्ति का वितरण समय पर होता रहा है। इससे गरीब और मध्यम आय वर्ग के छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रहने में काफी राहत मिलती है। मेधावी छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट वितरित कर सरकार उन्हें न केवल डिजिटली स्ट्रांग बना रही है बल्कि ज्ञान–विज्ञान से जुड़ने की उनकी अभिलाषा को नई उड़ान भी दे रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमेशा यह मानना रहा है कि माफिया संस्कृति कभी भी युवाओं को आगे नहीं बढ़ने देती। उसे तरक्की के नए सोपान पर चढ़ने नहीं देती। चाहे शिक्षा माफिया हों या नकल माफिया, खेल माफिया हों या ड्रग माफिया, युवा शक्ति के लिए घातक और बाधक ही साबित होते हैं। माफिया संस्कृति के विकास–विस्तार से सर्वाधिक नुकसान युवा शक्ति को ही होता है। मुख्यमंत्री यह बात जानते हैं कि किसी भी युवक के विकास में उसकी अभिरुचि का क्या महत्व होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में अगर उन्होंने शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया तो खेल नीति को भी उसी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाया।

खेलेगा देश, बढ़ेगा देश, का नारा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में प्रयासरत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ इसी से मिलता–जुलता नारा दिया। 'खेलेगा उत्तर प्रदेश– बढ़ेगा उत्तर प्रदेश।' उन्होंने प्रदेश के हर जिले में स्टेडियम बनवाने और हर गांव में खेल का मैदान विकसित करने की रणनीति बनाई। इसमें संदेह नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में युवा हितों को पर्याप्त तरजीह दी जा रही है और उनके हितों से खिलवाड़ करने वालों के प्रति सरकार का रुख बेहद सख्त भी है। उन पर प्रभावी कार्रवाई भी हो रही है। उनकी संपत्ति भी जब्त हो रही है और उस पर बुलडोजर भी चल रहे हैं।

देश और प्रदेश की खेल संस्कृति में आमूल–चूल परिवर्तन हुआ है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, सांसद व विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण लीग के जरिए खेल और खिलाड़ियों को बढ़ाने के सार्थक प्रयास हो रहे हैं। नई–नई प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में उत्तर प्रदेश नौ खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। उनमें से तीन खिलाड़ियों ने देश के लिए क्रमशः स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीते। उत्तर प्रदेश की खेल नीति के तहत देश के लिए मेडल जीतने वाले सरकारी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप सरकारी नौकरी दी जाती है। इन तीन खिलाड़ियों को भी जल्द ही सरकारी नौकरी देने की घोषणा मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं। अब तक 500 से अधिक खिलाड़ी पदक जीतकर राज्य में सरकारी नौकरी पा चुके हैं। खेल विभाग में सहायक निदेशक से लेकर यूपी पुलिस में डिप्टी एसपी तक का पद खिलाड़ियों को मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मानें तो एक माह में ही पुनश्च 500 पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को



यूपी पुलिस और अन्य विभागों में नौकरी मिल सकती है।

गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 2 करोड़ रुपये प्रोत्साहन स्वरूप मिलेंगे सो अलग। ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को 10 लाख और कॉमनवेल्थ व एशियाड में भाग लेने वालों को 5–5 लाख रुपये की सहायता सरकार के स्तर पर दी जाती है। युवाओं को आगे बढ़ाने की सरकार की यह मजबूत इच्छाशक्ति नहीं तो और क्या है? मौजूदा सरकार का मानना है कि खेल और खेल की संस्कृति को बढ़ाने के लिए सरकार के साथ समाज को आगे आना चाहिए। स्वयंसेवी संगठनों को भी युवाओं का उत्साहवर्धन करना चाहिए। सरकार तो निजी एकेडमी चलाने वालों को भी आर्थिक मदद देना चाहती है। वह इसलिए कि वे युवाओं को तराश रहे हैं। सरकार लुप्त हो चुकी अखाड़ा संस्कृति को पुनर्जीवित करने की दिशा में भी काम कर रही है। इस निमित्त वह पुराने अखाड़ों और उनके उस्तादों का जहां पंजीकरण कराना चाहती है, वहीं नए अखाड़ों की स्थापना भी करना चाहती है जिससे बड़ी तादाद में युवा पीढ़ी कुश्ती कला में पारंगत हो सके। सरकार की कोशिश है कि राज्य के युवा आधुनिक खेल सुविधाओं का लाभ पा सकें और पहलवानी में देश–दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम रौशन कर सकें।

उसकी कोशिश हर गांव में खेल मैदान विकसित करन और ओपेन जिम खोलने की है जिससे ग्रामीण युवा शारीरिक और बौद्धिक दोनों ही स्तरों पर देश–दुनिया में अपनी मजबूती का परिचय दे सकें। सरकार की कोशिश हर विकास खंड में मिनी स्टेडियम, हर जनपद में स्टेडियम, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज और हर स्पोर्ट्स कॉलेज में एकसेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की है।

इस सच को नकारा नहीं जा सकता कि पहले यूपी में एक भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं थी लेकिन अब सरकार के प्रयास से, दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण हो गया है। वहां पाठ्यक्रम भी शुरू हो गए हैं। नई–नई प्रतियोगिताएं वहां होने लगी हैं। युवा इस अवसर का लाभ ले भी रहे हैं। 2030 का कॉमनवेल्थ भारत में होने जा रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि इस यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी उसमें अपनी सफलता का परचम जरूर लहराएंगे। ◆



(लेखिका आईटी क्षेत्र की विशेषज्ञ हैं)
मो. : 6388573155

यूपी के विकास में जापान का साथ

—अनिल श्रीवास्तव

उत्तर प्रदेश–जापान निवेश सम्मेलन 2026 ने उत्तर प्रदेश और जापान के बीच आर्थिक, औद्योगिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संबंधों को एक नई दिशा प्रदान की है। अगस्त 2026 में आयोजित इस उच्चस्तरीय निवेश कार्यक्रम में 200 से अधिक जापानी सीईओ, उद्योग प्रतिनिधि, निवेशक और नीति–निर्माता शामिल हुए। नई दिल्ली से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों तक पहुंचे इस संवाद का उद्देश्य जापान की तकनीक, गुणवत्ता और निवेश क्षमता को उत्तर प्रदेश के विशाल बाजार, मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक संभावनाओं से जोड़ना रहा।

यह सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसे केवल निवेश आकर्षित करने वाले एक सामान्य आयोजन के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके केंद्र में उत्तर प्रदेश को जापानी उद्योगों के लिए भारत में एक 'दूसरा औद्योगिक घर' बनाने की व्यापक सोच दिखाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी कंपनियों से विनिर्माण के साथ–साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, स्किल सेंटर और ग्लोबल सप्लाई चेन में निवेश करने का आह्वान किया।

जापान विश्व में अपनी तकनीकी दक्षता, प्रिसिजन इंजीनियरिंग, गुणवत्ता, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस और 'काइजन' जैसी कार्यसंस्कृति के लिए जाना जाता है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश के पास विशाल बाजार, बड़ी युवा आबादी, मानव संसाधन, औद्योगिक भूमि, तेजी से विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर और देश के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक की ताकत है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी में स्वाभाविक पूरकता दिखाई देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसी पूरकता को रेखांकित करते हुए जापानी निवेशकों के सामने उत्तर प्रदेश की स्केल और जापान की तकनीकी क्षमता को साथ लाने का दृष्टिकोण रखा। इस साझेदारी का लक्ष्य केवल विदेशी पूंजी लाना नहीं बल्कि ऐसी औद्योगिक व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें जापानी तकनीक, भारतीय प्रतिभा और उत्तर प्रदेश का बाजार मिलकर वैश्विक उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला का मजबूत हिस्सा बनें।

इस निवेश सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में लगभग ₹3,191 करोड़ की जापान–संबंधित



परियोजनाओं का ग्राउंडब्रेकिंग/शुभारंभ रहा। इन परियोजनाओं से 10,000 से अधिक संभावित रोजगार अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यह पहल इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश की निवेश नीति अब केवल एमओयू और निवेश प्रस्तावों तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि निवेश को धरातल पर उतारने पर जोर दे रही है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा और स्पार्क माइंडा से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहा। इससे ऑटोमोबाइल, ऑटो-कंपोनेंट, इंजीनियरिंग और संबद्ध विनिर्माण क्षेत्रों में नई संभावनाओं के खुलने की उम्मीद है।



सम्मेलन में प्रस्तावित 500 एकड़ की 'जापानीज सिटी' भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। यीडा क्षेत्र में विकसित की जाने वाली इस परियोजना की परिकल्पना जापानी कंपनियों के लिए समर्पित औद्योगिक एवं आवासीय इकोसिस्टम के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य जापानी निवेशकों को केवल जमीन उपलब्ध कराना नहीं बल्कि उन्हें विश्वस्तरीय आधारभूत सुविधाएं, प्लग-एंड-प्ले व्यवस्था और व्यवसाय के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। इन्वेस्ट यूपी के अनुसार इस प्रस्तावित जापानी सिटी में जापानी निवेशकों के लिए औद्योगिक और आवासीय सुविधाओं का एकीकृत ढांचा विकसित करने की योजना है। यदि यह मॉडल सफल होता है तो उत्तर प्रदेश में जापानी कंपनियों के लिए एक ऐसा क्लस्टर तैयार हो सकता है, जहां उत्पादन, सप्लाई चेन, आवास, कौशल और व्यावसायिक सेवाएं एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा हों।

यह सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसे केवल निवेश आकर्षित करने वाले एक सामान्य आयोजन के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके केंद्र में उत्तर प्रदेश को जापानी उद्योगों के लिए भारत में एक 'दूसरा औद्योगिक घर' बनाने की व्यापक सोच दिखाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी कंपनियों से विनिर्माण के साथ-साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, स्किल सेंटर और ग्लोबल सप्लाई चेन में निवेश करने का आह्वान किया।

इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश-जापान सहयोग का दायरा पारंपरिक विनिर्माण से कहीं आगे बढ़ता दिखाई दिया। निवेश संवाद में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, रोबोटिक्स, मेडिकल टेक्नोलॉजी, आईटी और ग्लोबल कैपिबिलिटी सेंटर्स जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी तरह सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में जापानी तकनीकी विशेषज्ञता उत्तर प्रदेश की उभरती इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को नई मजबूती दे सकती है। यह परिवर्तन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को केवल बड़े पैमाने के पारंपरिक उद्योगों पर निर्भर रखने के बजाय हाई-टेक, हाई-वैल्यू और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग की ओर ले जाने की क्षमता रखता है।

किसी भी निवेश की वास्तविक सफलता तभी मानी जाती है, जब उसका लाभ जमीन पर रोजगार और आय के रूप में दिखाई दे। उत्तर प्रदेश-जापान साझेदारी का एक महत्वपूर्ण पक्ष स्किल डेवलपमेंट और रोजगार रहा। जापान की मैन्युफैक्चरिंग संस्कृति और कौशल-आधारित कार्यप्रणाली को उत्तर प्रदेश के युवा मानव संसाधन से जोड़ना राज्य के लिए बड़ा अवसर है। जापानी कंपनियों के साथ सहयोग से आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता नियंत्रण, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स,

इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार किया जा सकता है। सम्मेलन में रोजगार, कौशल विकास और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण को साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया। इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिल सकता है, जहां स्थानीय प्रतिभा को वैश्विक उद्योगों के अनुरूप कौशल देकर उन्हें प्रदेश में ही उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा मजबूत होगी।



उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में जापान की तकनीक और उत्तर प्रदेश की कृषि क्षमता का मेल फूड प्रोसेसिंग, एग्री–टेक, कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन और आधुनिक कृषि आधारित उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को देश का 'फूड बास्केट' बताते हुए कृषि और फूड प्रोसेसिंग में जापानी निवेश की संभावनाओं को विशेष रूप से रेखांकित किया। यदि इस क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और निवेश बढ़ता है तो इसका लाभ केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा। बेहतर प्रोसेसिंग, भंडारण और बाजार व्यवस्था किसानों की आय तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर सकती है।

इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भारत–जापान संबंध केवल आर्थिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार पर भी मजबूत हैं। उत्तर प्रदेश की बौद्ध विरासत जापान के साथ सांस्कृतिक संपर्क का महत्वपूर्ण आधार है। यामानाशी प्रीफेक्चर के साथ सहयोग इस संबंध को एक नए आयाम तक ले जा सकता है। पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और युवा आदान–प्रदान के क्षेत्र में सहयोग से आर्थिक साझेदारी को सामाजिक और मानवीय संबंधों से जोड़ा जा सकता है। सम्मेलन के दौरान यामानाशी को उत्तर प्रदेश पर्यटन के लिए जापान में एक महत्वपूर्ण प्रवेशद्वार बनाने की दिशा में भी चर्चा हुई। इससे वाराणसी, कुशीनगर, श्रावस्ती, अयोध्या और आगरा जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों को जापानी पर्यटकों और निवेशकों के बीच नई पहचान मिल सकती है।

जापानी निवेशक लंबे समय के लिए स्थिरता, गुणवत्ता, समयबद्धता और भरोसे को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे में किसी राज्य का केवल बड़ा बाजार होना पर्याप्त नहीं है। निवेशक को जमीन, बिजली, लॉजिस्टिक्स, अनुमति, सुरक्षा, कुशल श्रम और प्रशासनिक सहयोग की एक विश्वसनीय व्यवस्था चाहिए। उत्तर प्रदेश ने बीते वर्षों में



निवेश सुविधा के लिए इन्वेस्ट यूपी और निवेश मित्र जैसे तंत्रों को मजबूत किया है। जापानी निवेशकों के लिए विशेष जापान डेस्क तथा संस्थागत संपर्क व्यवस्था भी इसी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान और निवेश प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भरोसा सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक– प्रशासनिक संदेशों में से एक रहा।

उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बड़े पैमाने पर निजी एवं विदेशी निवेश, निर्यात, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, तकनीक और रोजगार का विस्तार



आवश्यक है। जापान जैसी तकनीकी और औद्योगिक शक्ति के साथ गहरी साझेदारी इस लक्ष्य को गति दे सकती है। इन्वेस्ट यूपी ने भी जापान के साथ साझेदारी को राज्य की 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश–जापान निवेश सम्मेलन 2026 को केवल एक निवेश सम्मेलन नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की वैश्विक आर्थिक भूमिका को विस्तार देने की रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए। इस सम्मेलन की वास्तविक उपलब्धि केवल निवेश के आंकड़ों में नहीं बल्कि विश्वास के नए रिश्ते में है। जापान को उत्तर प्रदेश में बाजार दिखाई देता है तो उत्तर प्रदेश को जापान में तकनीक, पूंजी और वैश्विक औद्योगिक अनुभव का साझेदार दिखाई देता है। जापान की 'क्वालिटी, प्रिसिसन और इनोवेशन' तथा उत्तर प्रदेश की 'स्केल, स्किल और मार्केट' का मेल आने वाले समय में एक मजबूत औद्योगिक मॉडल तैयार कर सकता है।

उत्तर प्रदेश–जापान निवेश सम्मेलन 2026 एक ऐसे समय में हुआ है जब उत्तर प्रदेश तेजी से राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश मानचित्र पर अपनी जगह मजबूत कर रहा है। सम्मेलन ने यह संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश अब केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ग्रीन एनर्जी और वैश्विक सप्लाई चेन का संभावित केंद्र है। यदि सम्मेलन में हुए समझौतों और निवेश प्रस्तावों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है तो आने वाले वर्षों में इसका असर उद्योग, रोजगार, कौशल, निर्यात, तकनीकी क्षमता और राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे सकता है।

इस पूरे आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका केवल मेजबान या औपचारिक प्रतिनिधि की नहीं बल्कि निवेश आकर्षित करने वाले नेतृत्वकर्ता, नीति के प्रस्तोता और उत्तर प्रदेश की नई औद्योगिक पहचान के ब्रांड एंबेसडर की रही। फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री के जापान दौरे और वहां जापानी उद्योग जगत के साथ संवाद ने इस साझेदारी को नई गति दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश और जापान की यह साझेदारी निवेश से आगे बढ़कर साझा विकास की साझेदारी बनती दिखाई दे रही है, जहां जापान की तकनीकी उत्कृष्टता और उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति, विशाल बाजार तथा औद्योगिक क्षमता मिलकर एक नए आर्थिक अध्याय की नींव रख सकती है। यही इस सम्मेलन का सबसे बड़ा संदेश है, उत्तर प्रदेश अब वैश्विक निवेश का केवल गंतव्य नहीं बल्कि वैश्विक औद्योगिक साझेदारी का सक्रिय केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ◆

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)
मो. : 9935097410

कांवड़ यात्रा : आस्था, परंपरा और संस्कृति का संगम

—रुचि शिशिर मिश्रा



भारत की सनातन परंपरा में यात्राएं केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, तप, संकल्प और ईश्वर से जुड़ने की साधना रही हैं। इन्हीं महान धार्मिक परंपराओं में कांवड़ यात्रा का विशेष स्थान है। सावन के पवित्र महीने में जब देशभर की सड़कों पर भगवा वस्त्रों में "हर हर महादेव" और "बोल बम" का जयघोष गूंजता है, तब पूरा उत्तर भारत शिवमय दिखाई देने लगता है।

कांवड़ यात्रा का मूल भाव भगवान शिव को पवित्र गंगाजल अर्पित करना है। श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के स्थानीय गंगा तटों जैसे कछला घाट (बदायूं), प्रयागराज (संगम), और गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़) से गंगाजल लेकर उसे कांवड़ में धारण करते हैं और पैदल यात्रा करते हुए शिवालयों में पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा श्रद्धा के साथ–साथ संयम, अनुशासन, सेवा और संकल्प की भी परीक्षा होती है।

कांवड़ यात्रा का मूल भाव भगवान शिव को पवित्र गंगाजल अर्पित करना है। श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के स्थानीय गंगा तटों जैसे कछला घाट (बदायूं), प्रयागराज (संगम), और गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़) से गंगाजल लेकर उसे कांवड़ में धारण करते हैं और पैदल यात्रा करते हुए शिवालयों में पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा श्रद्धा के साथ–साथ संयम, अनुशासन, सेवा और संकल्प की भी परीक्षा होती है।

कांवड़ यात्रा की धार्मिक मान्यता समुद्र मंथन की कथा से भी जुड़ी है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। मान्यता है कि भगवान



शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए गंगाजल अर्पित किया गया। सावन में गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक इसी भाव की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति माना जाता है। कांवड़ परंपरा के इतिहास के संबंध में अलग-अलग धार्मिक मान्यताएँ और ऐतिहासिक मत मिलते हैं। कुछ परंपराएँ इसकी शुरुआत भगवान परशुराम से जोड़ती हैं, जबकि ऐतिहासिक अध्ययनों में प्राचीन काल से जल लेकर शिव आराधना करने की परंपराओं के प्रमाणों का उल्लेख मिलता है। आधुनिक स्वरूप में कांवड़ यात्रा ने विशेष रूप से उत्तर भारत में व्यापक जनभागीदारी प्राप्त की है।

काशी विश्वनाथ : कांवड़ियों की आस्था का दिव्य केंद्र

उत्तर प्रदेश की धरती पर कांवड़ यात्रा की आध्यात्मिक पूर्णता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है काशी विश्वनाथ धाम। वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहां भगवान शिव "विश्वनाथ" अर्थात संपूर्ण विश्व के स्वामी के रूप में विराजमान हैं। मंदिर गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है और सदियों से भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रमुख केंद्र रहा है। वर्तमान मंदिर संरचना का निर्माण 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने कराया था। बाद में मंदिर के शिखरों पर स्वर्ण आभा ने इसकी दिव्यता को और बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में बना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कायाकल्प का प्रतीक है। 13 दिसंबर, 2021 को लोकार्पित नव्य भव्य धाम ने सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के साथ-साथ धार्मिक पर्यटन का नया अध्याय लिखा है। 4 साल में लगभग 26 करोड़ से अधिक शिवभक्तों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। काशी की आध्यात्मिक महिमा को संस्कृत के इस प्रसिद्ध श्लोक में अनुभव किया जा सकता है– "गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु।।' इसी के साथ "ॐ नमः शिवाय।" भगवान शिव के प्रति भक्त की सरल पुकार है। यही मंत्र कांवड़ियों की यात्रा का संबल बनता है और यही भाव उसे कठिन मार्ग पर आगे बढ़ाता है।

तप, संकल्प और पर्यटन अर्थव्यवस्था के लिए अवसर

साल 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में बेहतर बुनियादी ढांचे, उन्नत सड़क व हवाई कनेक्टिविटी और धार्मिक स्थलों के कायाकल्प से पर्यटन को अभूतपूर्व पंख लगे हैं। वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 156 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने राज्य का भ्रमण किया, जिससे उत्तर प्रदेश देश का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनकर उभरा है। कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और पर्यटन अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम, गंगा घाट, गंगा आरती और प्राचीन गलियां देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इसके साथ ही प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, चित्रकूट और विंध्य क्षेत्र जैसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल





उत्तर प्रदेश को एक विशाल आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग भी वाराणसी को प्राचीन, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तुत करता है। कांवड़ यात्रा के दौरान स्वच्छता, यातायात, स्वास्थ्य, विश्राम, सुरक्षा और डिजिटल सूचना जैसी सुविधाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए प्रशासन द्वारा रूट डायवर्जन, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी, जगह-जगह मेडिकल कैंप, मोबाइल शौचालय तथा डिजिटल हेल्प डेस्क जैसी व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं। होटल, धर्मशाला, परिवहन, हस्तशिल्प, स्थानीय खान-पान और धार्मिक सामग्री से जुड़े हजारों छोटे व्यवसाय इससे लाभान्वित होते हैं।

एकता और सनातन चेतना की गूंज

कांवड़ यात्रा वास्तव में भारत की उस जीवंत परंपरा का प्रतीक है, जिसमें धर्म और लोकजीवन एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक कांवड़िए के कंधे पर रखा गंगाजल केवल जल नहीं होता। उसमें उसका संकल्प, उसकी श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति उसकी आस्था समाहित होती है। जब यही यात्रा काशी पहुंचती है और गंगाजल बाबा विश्वनाथ को अर्पित होता है, तो यह क्षण भक्त और भगवान के बीच अद्भुत आध्यात्मिक संवाद बन जाता है। "हर हर महादेव" का उद्घोष केवल धार्मिक नारा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन चेतना की गूंज है। कांवड़ यात्रा इसी चेतना को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाती है और उत्तर प्रदेश को धर्म, संस्कृति, इतिहास और पर्यटन के एक अद्वितीय संगम के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने की अपार क्षमता रखती है।

कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा

गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर में कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति की "जीवन पाठशाला" है, जो करोड़ों श्रद्धालुओं को शिव भक्ति और सामाजिक समरसता के सूत्र में पिरोती है। उनकी सरकार इस यात्रा को "सेवा उत्सव" मानकर सुरक्षा, स्वच्छता और बेहतर सुविधाओं का सामन्वय सुनिश्चित करती है। इस सावन में भी सीएम योगी ने मेरठ की धरती पर भगवान शिव के प्रति आस्था में कांवड़ियों का पुष्पवर्षा से अभिनंदन किया। जैसे ही हेलिकॉप्टर से फूलों की वर्षा शुरू हुई, कांवड़ियों ने आभार प्रकट किया. योगी आदित्यनाथ का यह बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि "मेरा सरकारी हेलीकॉप्टर ले जाओ, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करो", वास्तव में उनकी धार्मिक आस्था और परंपराओं के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। यह कदम न केवल श्रद्धालुओं के उत्साह को बढ़ाता है, बल्कि सरकार की ओर से धार्मिक आयोजनों के प्रति समर्थन का भी संदेश देता है। ◆

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)
मो. : 8318392949

उत्तर प्रदेश में एआई क्रांति

—डॉ. ऋतु दुबे तिवारी



उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को डिजिटल और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कई ऐतिहासिक पहलों की शुरुआत की है। बजट 2026–27 के दौरान घोषित इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के लाखों युवाओं को मुफ्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा एनालिटिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित कर उन्हें भविष्य की जरूरतों के अनुकूल तैयार करना है।

'AI for UP' और कौशल विकास योजना (चरण–2)

युवाओं के लिए मुफ्त तकनीकी प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'AI for UP' कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं :

- **3 घंटे का विशेष कोर्स :** 'AI for UP' के तहत युवाओं के लिए 3 घंटे का मुफ्त ऑनलाइन ट्रेनिंग और असेसमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है।
- **अनिवार्य AI शिक्षा :** कौशल विकास निधि (SSDF) के दूसरे चरण में 936 प्रशिक्षण प्रदाताओं के जरिए 1 लाख से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें हर बैच के लिए 4 घंटे का 'AI for All' और सॉफ्ट स्किल मॉड्यूल अनिवार्य किया गया है।
- **विशाल लक्ष्य :** योजना के माध्यम से राज्य के 1.5 लाख से अधिक युवाओं को मुफ्त एआई ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि 25 लाख कामकाजी युवाओं को मुफ्त एआई टूल्स उपलब्ध कराने की योजना है।
- **प्लेसमेंट और ट्रैकिंग :** कोर्स में 70 प्रतिशत या अधिक उपस्थिति वाले छात्र ही रोजगार मेले में शामिल हो सकेंगे। प्रशिक्षण संस्थाओं को परिणाम घोषित होने के 90 दिनों के भीतर प्लेसमेंट कराना होगा और अगले 365 दिनों तक ट्रैकिंग की जाएगी।



बजट 2026–27 : यूपी AI मिशन और तकनीकी बजट का आवंटन

विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाने के लिए सरकार ने बजट में भारी–भरकम धनराशि का प्रावधान किया है :

- **यूपी AI मिशन (₹225 करोड़) :** शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सुशासन में एआई–आधारित समाधान विकसित करने के लिए ₹225 करोड़ का बजट तय किया गया है।
- **रोबोटिक और ड्रोन मिशन (₹100 करोड़) :** जोखिम वाले कार्यों, कृषि में



कीटनाशकों के छिड़काव और भारी भार उठाने जैसे कामों को आसान बनाने के लिए रोबोटिक मिशन को ₹100 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

- **डेटा सेंटर इकोसिस्टम (₹100 करोड़)** : प्रदेश को सुरक्षित डिजिटल हब बनाने और 2030 तक डेटा सेंटर इकोसिस्टम तैयार करने के लिए डेटा अथॉरिटी के गठन हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान है।
- **स्टार्टअप्स के लिए यू–हब** : लखनऊ में स्थापित होने वाला यू–हब्श राज्य के टेक–स्टार्टअप्स को संसाधन, मेंटरशिप और निवेश के अवसर प्रदान करेगा।

कृषि और आपदा प्रबंधन में AI का उपयोग

एआई का दायरा केवल आईटी तक सीमित न रखकर कृषि, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन में भी बढ़ाया जा रहा है। कृषि में सटीक खेती, मौसम पूर्वानुमान और फसलों पर कीट हमलों की पूर्व चेतावनी के लिए एआई का उपयोग होगा। वहीं, आकाशीय बिजली और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए सैटेलाइट सेंसर और पूर्व चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था की जा रही है।

तकनीकी शिक्षा, रोबोटिक्स और एआई मिशन जैसी योजनाओं के बल पर उत्तर प्रदेश तकनीक आधारित समग्र विकास की दिशा में एक नया अध्याय लिख रहा है।

- **ग्लोबल पार्टनरशिप (AI Pragya)** : Microsoft, Google, Intel और IBM जैसी प्रमुख टेक कंपनियों के सहयोग से AI Pragya प्रोग्राम के तहत प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों, किसानों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में AI पहल को लागू करने की मुख्य चुनौतियां

इंफ्रास्ट्रक्चर और काम को पूरा करने में रुकावटें : निवेशकों की कड़ी जांच–पड़ताल : भरोसेमंद और अरबों डॉलर का निवेश हासिल करना मुश्किल बना हुआ है। उदाहरण के लिए, राज्य को एक AI स्टार्टअप के साथ ₹25,000 करोड़ का बड़ा MoU रद्द करना पड़ा क्योंकि मानक वित्तीय समीक्षा में उनकी नेट वर्थ कम पाई गई और काम पूरा करने में जोखिम दिखे।

कंप्यूट पावर की कमी : नोएडा और लखनऊ जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर डीप–टेक सिस्टम विकसित करने के

लिए बहुत बड़े डेटा सेंटर और भारी AI कंप्यूटिंग क्षमता की जरूरत होती है, जो अभी भी बन रहे हैं।

ग्रामीण डिजिटल अंतर : जबकि शहरी केंद्र तेजी से बढ़ रहे हैं, ग्रामीण जिलों में बिना रुकावट वाले हाई–स्पीड इंटरनेट और तकनीक तक पहुंच की कमी के कारण पूरे राज्य में इसे एक समान रूप से लागू करने में बाधा आती है।

खेती का बिखराव : UP की 70 प्रतिशत से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है। खेती की निगरानी या सब्सिडी वितरण में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए AI का इस्तेमाल करने में जमीन के छोटे–छोटे टुकड़ों और ट्रैकिंग में अक्षमता के कारण देरी होती है।

हेल्थकेयर इंटरऑपरेबिलिटी : फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए AI–सक्षम डायग्नोस्टिक नेटवर्क बनाने के लिए उच्च–गुणवत्ता वाले, स्टैंडर्ड मेडिकल डेटा की जरूरत होती है, जो ग्रामीण क्लीनिकों और जिला अस्पतालों में अलग–अलग और बिखरा हुआ है।

लालफीताशाही : प्रशासनिक विभागों को पुराने, कागज–आधारित गवर्नेंस से AI–सक्षम, ऑटोमेटेड निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में बदलने में मजबूत आंतरिक संस्थागत विरोध का सामना करना पड़ता है।

टैलेंट और भाषायी चुनौतियां : AI साक्षरता का अंतर : बड़ी युवा आबादी को AI–तैयार वर्कफोर्स में बदलना एक बहुत बड़ा काम है। 'AI प्रज्ञा' जैसे कार्यक्रमों का लक्ष्य 10 लाख युवाओं को कौशल सिखाना है, लेकिन पूरे राज्य में स्कूल के सिलेबस को अपडेट करने की प्रक्रिया धीमी है और अभी ड्राफ्ट स्टेज पर है।

भाषायी विविधता : AI सिस्टम को स्थानीय बोलियों की बारीकियों को समझने में मुश्किल होती है। बातचीत करने वाले AI प्लेटफॉर्म (जैसे SwiftChat) को क्षेत्रीय शिक्षकों और नागरिकों के लिए प्रभावी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर लोकलाइजेशन की जरूरत होती है।



AI सिस्टम को बेहतर और सशक्त तरीके से जमीन पर उतारा जा सके और आने वाले समय में जब ए आई का महत्व हर दिन बढ़ता जा रहा है ऐसे में उत्तर प्रदेश के युवाओं को विशिष्ट प्रशिक्षण देकर उन्हें कदम से कदम मिलाकर भारत के विकास की दिशा में उत्तरोत्तर वृद्धि में महती भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है। यह प्रयास करने के लिए यूपी सरकार पूर्णतया प्रतिबद्ध है। चुनौतियां तमाम है लेकिन इसके बीच भी बहुत सारी आशाओं का उजाला है और उम्मीद की जा रही है कि तमाम चुनौतियों से निपटते हुए यह प्रोग्राम न सिर्फ बजट की दृष्टि से बल्कि जमीनी स्तर पर भी देश सभी सपनों को साकार करने वाला सिद्ध होगा। ◆

(लेखिका साइबर विशेषज्ञ और निर्स्कॉर्ट मीडिया कॉलेज गाजियाबाद की प्रिंसिपल हैं)
मो. : 9650450604

देश की रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाता यूपी

– सियाराम पांडेय 'शांत'

देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसके लिए सीमाओं की सुरक्षा जरूरी है। जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रहतीं, उसकी आर्थिक समृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। यह सच है कि मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार पूरी दुनिया को यह संदेश देने में कामयाब रही है कि यह 1962 का भारत नहीं है। यह 2026 का भारत है जो अपने दुश्मन को घर में घुसकर मारता है और इसका उसने कई बार प्रमाण भी दिया है। सबका साथ,सबका विकास,सबका विश्वास और सबका साथ की रीति–नीति पर चलते हुए भारत आज न केवल विकास के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है,बल्कि विकसित भारत बनने की दिशा में भी कृतसंकल्प है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इससे पाकिस्तान की कमर तो टूटी ही, उसके सहयोगी देश भी कम परेशान नहीं हुए। भारत अल्प समय में भले ही इस युद्ध से अपना लक्ष्य पूर्ण कर बाहर आ गया हो लेकिन उच्च स्तर पर यह बात शिद्दत से महसूस की गई कि उसके रूस और इजराइल जैसे प्रमुख सहयोगी मित्र देश भी उसी समय युद्ध में फंसे होने की वजह से लंबी अवधि तक उसे सैन्य सामग्री आपूर्त करने में संभवतः सहज नहीं थे। इसलिए मोदी सरकार ने निर्णय लिया कि वह न केवल अपने देश में युद्धोपयोगी सामग्री का निर्माण करेगी और दुनिया भर के अपने मित्र देशों को उनका निर्यात भी करेगी। भारत सरकार ने इस दिशा में तत्काल प्रभाव से काम करना आरंभ किया।

उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जमीन इसी भावभूमि के तहत तैयार हुई। उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ सरकार ने सैनिकों के आत्मबल को बनाए रखने और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरे मनोयोग से इस योजना को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा के लिए न केवल समयबद्ध ढंग से भूमि उपलब्ध कराई,बल्कि रक्षा उत्पादन कंपनियों की हौसला अफजाई का एक भी अवसर अपने हाथ से जाने नहीं दिया। यही वजह है कि यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अब तक लगभग 39,571 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और 2,095 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।

यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण शुरू हो चुका है। यहां एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में भी इजाफा हो रहा है,जबकि कानपुर नोड में एम्युनेशन (गोला–बारूद) और हथियारों का निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसे साल के अंत तक और बढ़ाने का लक्ष्य है। अलीगढ़ नोड में ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है।



वहीं झांसी में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और अन्य कंपनियों द्वारा मिसाइल निर्माण व रक्षा उपकरणों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। धर्म नगरी चित्रकूट भी इन दिनों देश के लिए रक्षा उत्पादन की जमीन बनने की तैयार है। चित्रकूट नोड्स पर भी भूमि आवंटन और बुनियादी ढांचा विकास का काम तेजी से चल रहा है। देखा जाए तो डिफेंस कॉरिडोर के विभिन्न नोड्स पर कम से कम 9 प्रमुख औद्योगिक इकाइयों ने अब पूरी तरह से उत्पादन आरंभ कर दिया है। जिस शहर में कभी सिर्फ चमड़े का काम होता था या छोटे कारखाने हुआ करते थे, वहां अब मिसाइल और लड़ाकू जहाजों के पुर्जे बन रहे हैं,यह देश और प्रदेश के लिए अपने आप में बड़ी उपलब्धि है।कभी भारत की गणना विश्व के सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों में होती थी।

वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी करीब साढ़े नौ फीसदी तक पहुंच चुकी थी। अब हालात बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश गुजरात और तमिलनाडु की तरह ही रक्षा उत्पादन उद्योग का बड़ा हब बनकर उभर रहा है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक ऐसी योजना है जो लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, आगरा और चित्रकूट को भारत के रक्षा उत्पादन का नया इंजन बना रही है।

गौरतलब है कि वर्ष 2018–19 के केंद्रीय बजट में इस कॉरिडोर की घोषणा हुई थी। भारत को हथियार और रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भर रहने की बजाय, खुद अपने देश में उन्हें बनाना ही इस योजना का लक्ष्य था। इस पूरी परियोजना को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी गई है। इस निमित्त उत्तर प्रदेश के छह शहरों को चुनने की एक वजह यह भी थी कि रक्षा उत्पादन सिर्फ एक जगह सिमटा न रहे, बल्कि राज्य के अलग–अलग हिस्सों में इसी बहाने रोजगार और विकास की किरण पहुंचे।

उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जमीन इसी भावभूमि के तहत तैयार हुई। उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ सरकार ने सैनिकों के आत्मबल को बनाए रखने और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरे मनोयोग से इस योजना को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा के लिए न केवल समयबद्ध ढंग से भूमि उपलब्ध कराई,बल्कि रक्षा उत्पादन कंपनियों की हौसला अफजाई का एक भी अवसर अपने हाथ से जाने नहीं दिया। यही वजह है कि यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अब तक लगभग 39,571 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और 2,095 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।

यह बताना भी मुनासिब होगा कि 11 अगस्त, 2018 को अलीगढ़ में आयोजित निवेशक सम्मेलन में ही 3,700 करोड़ से अधिक के निवेश की घोषणा हो गई थी। जून 2026 की रिपोर्ट पर गौर करें तो इस कॉरिडोर को अब तक निवेश प्रस्तावों के आंकड़ा 39,571 करोड़ हो गया है. सरकार अब इसे बढ़ाकर आने वाले सालों में करीब 1 लाख करोड़ तक ले जाने की दिशा में सचेष्ट है।

यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लिए अब तक करीब 2,040 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जा चुकी है, जिसमें से करीब 978 हेक्टेयर (आधे से थोड़ा कम) कंपनियों को आवंटित की जा चुकी है। कुल 62 कंपनियों को इस निमित्त जमीन मिल चुकी है, और इनमें से नौ इकाइयां पूरी तरह चालू भी हो चुकी हैं, जबकि 11 और के लिए लीज डील पर काम चल रहा है। कानपुर इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा निवेश केंद्र है, जहां करीब 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट आ चुके हैं. यहां अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने करीब 1,500 करोड़ की लागत से दो बड़ी फैक्ट्रियां लगाई हैं, जो गोला–बारूद और मिसाइल बनाएंगी । इन फैक्ट्रियों की गणना दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी निजी रक्षा निर्माण इकाइयों में होती है। ये दोनों फैक्ट्रियां फरवरी 2024 से ही संचालन में आ चुकी हैं, जबकि कॉरिडोर के झांसी नोड को 'गोला–बारूद और विस्फोटक केंद्र' के रूप में विकसित किया जा रहा है, और यहां 11,700 करोड़ का निवेश प्राप्त हो चुका है। यहां भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की नई यूनिट में रॉकेट प्रोपेलेंट और ग्रैड रॉकेट बनने हैं। इस नोड में 16 कंपनियों को 531 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन आवंटित की गई हैं। यहां

विस्फोटक, प्रोपल्शन सिस्टम और इन्फैंट्री हथियारों के मोबाइल प्लेटफॉर्म निर्मित किए जाएंगे।

लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहां ब्रह्मोस एयरोस्पेस की फैक्ट्री लग रही है। इसमें तकरीबन 300 करोड़ का निवेश हुआ है। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल जिसका कहर पाकिस्तान झेल चुका है और जिसे पाने के लिए अमेरिका तक लालायित है, उसका निर्माण लखनऊ में हो रहा है। इसके अलावा एरोलॉय टेक्नोलॉजीज यहां एयरोस्पेस के पुर्जों के लिए अत्यंत जरूरी समझे जाने वाले टाइटेनियम की कास्टिंग बनाएगी। इस निमित्त 320 करोड़ का निवेश मिल चुका है। देखा जाए तो लखनऊ नोड में अब तक करीब 4,850 करोड़ का निवेश हस्तगत हो चुका है। 12 से अधिक कंपनियां देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के महा अभियान में जुट गई हैं।

अलीगढ़ में बहुत तेजी के साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और ड्रोन बनाने का काम चल रहा है। अमिटेक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां यहां इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और सैटेलाइट सिस्टम का निर्माण कर रही हैं । इस निमित्त 330 करोड़ का निवेश हो चुका है, जबकि कुछ कंपनियां छोटे हथियार और सटीक कल–पुर्जों के निर्माण में लगी हुई हैं। अलीगढ़ नोड में अब तक 4,500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। चित्रकूट में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को करीब 75 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है, जहां रडार और एयर डिफेंस सिस्टम बनाए जाएंगे। इस परियोजना पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लगभग 562 करोड़ का निवेश कर रही है।

आगरा नोड अभी विकास के शुरुआती दौर में है। यहां जमीन आवंटन और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर की सबसे बड़ी ताकत और विशेषता इसकी कनेक्टिविटी है। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आने वाला गंगा एक्सप्रेसवे सभी छह नोड्स को परस्पर जोड़ते हैं। इसका सीधा फायदा यह है कि कच्चा माल और तैयार सामान तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, जिससे कंपनियों का समय और लागत दोनों बचेगी। इसका असल असर तो यह होगा कि यहां रोजगार में वृद्धि होगी। इंजीनियर, टेक्नीशियन, मजदूर और छोटे कारोबारियों को इससे लाभ मिलेगा। कानपुर और झांसी जैसे शहरों में लोगों को बड़ी तादाद में रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इस हेतु नए मौके बन रहे हैं। बड़ी सरकारी कंपनियों के साथ–साथ कई नए प्लेयर्स भी इस कॉरिडोर से जुड़कर आगे बढ़ सकेंगे। इसके आपूर्ति चक्र से जुड़कर छोटे उद्योगों को भी फायदा होना तय है।

धीरे–धीरे ही सही, मगर मजबूती से उत्तर प्रदेश के रक्षा गलियारे में आयुध उपकरणों और हथियारों का उत्पादन शुरू हो गया है।अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के कानपुर



सेंटर में फिलहाल करीब 2,000 कुशल और अकुशल कर्मचारी काम कर रहे हैं। प्रस्तावित विस्तार के बाद रोजगार के और नए अवसर सृजित हो सकते है। कानपुर स्थित इस डिफेंस एम्युनेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हर साल करीब 15 करोड़ राउंड विभिन्न स्तर की गोलियों का उत्पादन किया जा रहा है। इस निर्माण क्षमता को साल के अंत तक बढ़ाकर करीब 30 करोड़ करने का कंपनी की कोशिश है। कंपनी 2027 तक सालाना 40 लाख यूनिट ग्रेनेड उत्पादन की क्षमता हासिल करने के पक्ष में है। 2029 तक इसमें 40 लाख यूनिट की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाई जाएगी।

कुल मिलाकर अगर यह कहें कि सब कुछ अगर इसी तरह चलता रहा तो भारत न केवल स्वदेशी हथियारों के उत्पादन क्षेत्र में एक बड़ा नाम होगा बल्कि रक्षा उत्पादों के मामले में उसकी विकसित देशों पर बेवजह निर्भरता भी घटेगी। वह दुनिया में रक्षा उत्पादों के बड़े आयातक होने की बजाय बड़े निर्यातक होने का गौरव हासिल कर सकेगा और इन सबमें उसका सबसे बड़ा सम्बल बनेगा उत्तर प्रदेश जो देश के बदलते एयरोस्पेस और डिफेंस इकोसिस्टम में एक अहम खिलाड़ी बनकर उभर रहा है।

यह बताना ज्यादा मुफीद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रिय निगरानी में अब तक कॉरिडोर के लिए कुल 197 एमओयू साइन हो चुके हैं, जिनमें 172 औद्योगिक एमओयू हैं। इन सभी एमओयू के जरिए 34,844. 49 करोड़ रुपए का प्रस्तावित निवेश आ रहा है, जिससे प्रदेश में 52,658 नौकरियां सृजित होने की संभावना है। अगले चरण में 110 से अधिक कंपनियों के साथ एमओयू की प्रक्रिया लंबित है। इन 110 प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों से 22,847 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हो सकता है और 38,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप डिफेंस कॉरिडोर तेजी से प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे 'एक जिला–एक उत्पाद' और 'मेक इन इंडिया' के साथ जोड़ते हुए अनेक अवसरों पर कहा है कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर न सिर्फ उत्तर प्रदेश को, बल्कि पूरे देश को रक्षा विनिर्माण का ग्लोबल हब बनाएगा। डिफेंस कॉरिडोर के जरिए प्रदेश अब रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों को कड़ी टक्कर दे रहा है। आने वाले कुछ महीनों में और बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, जिससे उत्तर प्रदेश 'ट्रिलियन डॉलर इकॉनामी' के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है।

यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में विदेशी कंपनियां भी निवेश कर रही हैं। स्पेन की रक्षा क्षेत्र की कंपनियां डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश करने की योजना बना रही हैं। जल्द ही स्पेन का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के दौरे पर आ सकता है। निवेश के लिए एमओयू पर साइन कर सकता है। यूपीडा की मानें तो स्पेन की कंपनियों ने कानपुर और झांसी नोड में निवेश की इच्छा जाहिर की है। स्पेन की रक्षा और एयरोस्पेस कंपनियों को यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश का आमंत्रण देने के पीछे सिर्फ पूंजी आकर्षित करने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि प्रदेश को हाई–टेक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना है।

विकथ्य है कि स्पेन की प्रमुख रक्षा कंपनियां सैन्य परिवहन विमान, युद्धपोत, पनडुब्बियां, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, साइबर डिफेंस समाधान और बख्तरबंद वाहनों का निर्माण करती हैं।

यूपी डिफेंस कॉरिडोर में प्लांट स्थापित करने के लिए ये कंपनियां कुछ भारतीय कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर भी कर सकती हैं। सरकार का मानना है कि पूरी विशेषज्ञता और गुणवत्ता के साथ इस कॉरिडोर में सैन्य साजो सामान का निर्माण हो, जिससे भारत का गौरव बढ़े। सरकार इस मामले में हर कदम फूंक कर उठा रही है। पूर्ण संतुष्टि और प्रभावी छानबीन के साथ ही वह विदेशी कंपनियों को अपने भरोसे का साथी बना रही है क्योंकि सरकार भरोसे के टूटने के खतरे को बखूबी जानती और समझती है।

उम्मीद की जा सकती है कि देश को रक्षा उत्पादों के मामले में, सेना को और अधिक मजबूती देने के मामले में उत्तरप्रदेश मील के पत्थर की भूमिका अदा करेगा। डिफेंस कॉरिडोर यूपी की आर्थिक और औद्योगिक तस्वीर ही नहीं बदलेगा, अपितु विकसित भारत के महा अभियान में मजबूती से खड़ा नजर आएगा। उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा है, इस अवधारणा को साकार भी करेगा। ◆

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)
मो. : 7459998968



महिला सुरक्षा और सम्मान पर जोर

–सुरेन्द्र अग्निहोत्री

महिला सशक्तीकरण केवल एक नारा नहीं, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी (आत्मनिर्भर) बनाकर उनके वास्तविक स्वाभिमान और सम्मान को स्थापित करने की एक मजबूत पहल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में हुई है। महिलाएं जब आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, तो समाज और परिवार में उनका निर्णय लेने का अधिकार और आत्मसम्मान स्वतः बढ़ जाता है। इसी सूत्र वाक्य को साकार करने की दिशा में प्रदेश सरकार की घरौनी योजना ने आमूलचूल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। गौरतलब है कि स्वामित्व योजना के अन्तर्गत गांवों में एक करोड़ से अधिक महिलाओं के नाम घरौनी की गयी है। महिलाओं को सम्पत्ति पंजीकरण शुल्क में छूट दी गयी है। पुरानी मान्यता के अनुसार गांव की बेटी को सबकी बेटी माना जाता है। उसे जीने तथा आगे बढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। आज यह चीजें वास्तविकता में होती हुई दिखाई देती हैं। पहले प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी। सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन मिशन शक्ति की थीम है।

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में 62 लाख महिलाओं को आवास उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त और समृद्धशाली बना रही है। उन्हें रोजगार के साथ जोड़ रही है। प्रदेश की सशक्त नारी शक्ति स्वावलम्बन की ओर अग्रसर है। प्रदेश की सुदृढ़ कानून–व्यवस्था के कारण हमारी बेटियां स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही हैं।प्रदेश में अलग–अलग क्षेत्रों में संचालित लगभग 20 हजार स्टार्टअप में से आधे से अधिक महिलाओं द्वारा संचालित हैं।

सुरक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है। आत्मविश्वास उसे आत्मगौरव की अनुभूति कराता है और आत्मगौरव का भाव ही व्यक्ति को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर करता है। यह आत्मनिर्भरता ही विकसित भारत की संकल्पना का आधार बनेगा। आज प्रदेश की प्रत्येक बेटी स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही है। प्रदेश पुलिस बल में 20 प्रतिशत बेटियों को आरक्षण दिया गया है। महिलाओं के लिए तीन नई बटालियन गठित की गयी हैं और तीनों के नाम भारत एवं उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति की प्रतीक वीरांगना ऊदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई और वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर रखे गये हैं। इसके अतिरिक्त, तीन नई

महिला बटालियन के गठन की प्रक्रिया भी सरकार आगे बढ़ा रही है। विगत 11 वर्षों में महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में स्वावलम्बन की दिशा में अग्रसर हुई हैं। पहले प्रधानमंत्री आवास न होने से सबसे अधिक महिलाएं पीड़ित होती थीं। घर में शौचालय नहीं होने पर सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती थीं। घर में रसोई गैस न होने पर सर्वाधिक पीड़ा महिला को झेलनी पड़ती थी, क्योंकि कई बार घर के सभी सदस्यों के लिए समय पर भोजन बनाने के लिए ईंधन नहीं होता था। जैसे–तैसे वह भोजन बनाती थीं। अब उनके पास 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' का कनेक्शन है। सरकार 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के प्रत्येक लाभार्थी को वर्ष में दो बार, होली और दीपावली पर, निःशुल्क रसोई गैस के रिफिल सिलेण्डर उपलब्ध कराती है।



डबल इंजन सरकार द्वारा 01 करोड़ 06 लाख से अधिक निराश्रित महिला, वृद्धजन और दिव्यांगजन को 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। इसमें वृद्धि की दिशा में भी सरकार मंथन कर रही है।

महिलाओं को नयी योजनाएं

वर्ष 2026–27 के बजट में हम अनेक नई योजनाएं लेकर आये हैं। युवा, महिला, अन्नदाता किसान और गरीब पर आधारित बजट में इन सभी लोगों के उत्थान के लिए व्यवस्था की गयी है। बजट में महिलाओं के लिए कुछ स्कीम बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अन्तर्गत 05 लाख रुपये तक ऋण की व्यवस्था की गयी है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं, जिन्हें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इससे ज्यादा ऋण चाहिए। उन्हें अपने घर के कार्य के लिए कम पैसे का ऋण चाहिए। इस बार के बजट में इसकी व्यवस्था की गयी है। बजट में प्रदेश सरकार ने महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है। यह केन्द्र सरकार की शी–मार्ट योजना से प्रेरित है। योजना के माध्यम से महिला स्वयंसेवी समूहों द्वारा बनाये गये उत्पादों को बाजार तक आसान पहुंच प्राप्त होगी।

महिलाओं के लिए हॉस्टल

गांव या दूरदराज से आने वाली बेटी के लिए सरकार ने विभिन्न जनपदों में ऐसे छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है, जहां वे सुरक्षा के साथ आराम से रह सकें।

कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की स्थापना की जा रही है। प्रत्येक हॉस्टल की क्षमता 500 होगी। 500 की क्षमता वाले छात्रावास वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और आगरा में बनाए जा रहे हैं। इस बार के बजट में इसके लिए धनराशि आवंटित कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त, अयोध्या, बरेली, अलीगढ़, मीरजापुर, सहारनपुर, मुरादाबाद जनपद में भी सरकार ने इस बजट में धनराशि की व्यवस्था की है, ताकि बेटियों को किसी प्रकार की समस्या न होने पाए।

'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना'

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' से अब बेटी किसी पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि जन्म लेने से लेकर उसकी स्नातक तक की पढ़ाई के लिए प्रदेश सरकार 25 हजार



रुपये का पैकेज प्रदान कर रही है। वर्तमान में प्रदेश की 27 लाख बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं।

'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना'

'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के अन्तर्गत राज्य सरकार बेटियों के विवाह के लिए 01 लाख रुपये प्रदान कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 04 लाख से अधिक बेटियों का विवाह सम्पन्न किया जा चुका है।

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लॉन्च के अन्तर्गत प्रारम्भ में स्नातक व परास्नातक अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत मेधावी बेटियों को स्कूटी उपलब्ध करायी जायेगी। धीरे–धीरे अन्य बेटियों को इसके साथ जोड़ा जायेगा। यह योजना नारी शक्ति के क्रमिक उत्थान का उदाहरण है।

आवास योजना में 62 लाख महिलाओं को आवास

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में 62 लाख महिलाओं को आवास उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त और समृद्धशाली बना रही है। उन्हें रोजगार के साथ जोड़ रही है। प्रदेश की सशक्त नारी शक्ति स्वावलम्बन की ओर अग्रसर है। प्रदेश की सुदृढ़ कानून–व्यवस्था के कारण हमारी बेटियां स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही हैं।प्रदेश में अलग–अलग क्षेत्रों में संचालित लगभग 20 हजार स्टार्टअप में से आधे से अधिक महिलाओं द्वारा संचालित हैं।

न्याय पंचायतों में केवल महिलाएं

वर्ष 2026–27 के बजट में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर



पर डिजिटल इण्टरप्रेन्योर की स्थापना करने की एक नई स्कीम शुरू की गयी है। प्रदेश में 8,000 न्याय पंचायत हैं, जिसमें से 4,000 से अधिक न्याय पंचायतों में केवल महिलाएं भर्ती होने वाली हैं।

अंतर साफ है 70 साल में 10,000 तो 9 साल में तीन गुने से अधिक प्रदेश पुलिस बल में 20 प्रतिशत बेटियों को आरक्षण दिया गया है। वर्ष 1947 से वर्ष 2017 तक प्रदेश पुलिस में कुल 10,000 महिला कार्मिक थीं। अब इनकी संख्या कई गुना बढ़कर 44,000 से अधिक हो गयी है। यह संख्या बताती है कि योगी सरकार की दिशा महिलाओं के प्रति कितनी सकारात्मक हैं।



योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्थायी सरकार, मजबूत अधोसंरचना और निवेश अनुकूल नीतियों से नारी का सम्मान बड़ा है। नारी स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रही है, और सम्पूर्ण समाज स्वावलम्बन के पथ पर अग्रसर हो रहा है। प्रदेश की प्रत्येक नारी स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो रही है। सरकार जब निराश्रित महिलाओं के साथ खड़ी होती है, तो वह महिला स्वावलम्बन का एक मॉडल बनाती है। वर्तमान में प्रदेश में 36 से 37 प्रतिशत महिलायें अलग–अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। यह महिला सुरक्षा का सबसे अच्छा मॉडल उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है। ◆

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)
मो. : 9415508695



युवाओं का भविष्य और बदलते अवसर

—समर्थ आर्या

आज जब कोई युवा अपने भविष्य के बारे में सोचता है, तो उसके मन में क्या आता है? किसी के लिए यह डिग्री के बाद पहली नौकरी हो सकती है। किसी और के लिए यह अपना स्टार्ट–अप शुरू करना, तकनीक के क्षेत्र में करियर बनाना, किसी खेल टीम में स्थान पाना या अपनी कोई नई पहल शुरू करने का अवसर हो सकता है। भविष्य को लेकर युवाओं की यह बदलती सोच उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। देश की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले प्रदेश की प्रगति इस बात से गहराई से जुड़ी है कि उसके युवा क्या सीखते हैं, क्या सृजित करते हैं और समाज में क्या योगदान देते हैं। एक पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार करना केवल शिक्षा या कार्यबल में प्रवेश करने वाले युवाओं की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि युवा के पास विकल्प हों। पढ़ाई करने का विकल्प, नया कौशल सीखने का विकल्प, रोजगार पाने का विकल्प, उद्यम शुरू करने का विकल्प, पारंपरिक रास्तों से अलग करियर चुनने का विकल्प या अपने घर के पास ही कोई अवसर तैयार करने का विकल्प। उत्तर प्रदेश सरकार का युवा विकास के प्रति दृष्टिकोण इसी व्यापक समझ को दर्शाता है। शिक्षा और डिजिटल पहुंच को मजबूत करने से लेकर कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और खेलों के विस्तार तक, ध्यान ऐसे अनेक रास्ते बनाने पर है जिनके माध्यम से युवा अपनी आकांक्षाओं को अवसरों में बदल सकें।

अधिकांश युवाओं के लिए भविष्य की ओर पहला बड़ा कदम शिक्षा से शुरू होता है। पहली नौकरी के आवेदन या किसी व्यावसायिक विचार से बहुत पहले एक कक्षा, एक परीक्षा, एक पाठ्यक्रम या कोई कौशल उस यात्रा की शुरुआत बनता है जो आगे बढ़ती है। लेकिन आज शिक्षा उतनी ही तेजी से बदल रही है जितनी तेजी से वह दुनिया बदल रही है जिसमें युवा प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। सीखना अब केवल पाठ्यपुस्तकों या स्कूल–कॉलेज की समय–सारिणी तक सीमित नहीं है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और डिजिटल बुनियादी ढांचे तक पहुंच युवाओं को बदलते भविष्य के लिए तैयार करने का महत्वपूर्ण हिस्सा है।



उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा—तीनों स्तरों पर अपने शैक्षिक तंत्र का विस्तार किया है। स्कूल स्तर पर राज्य 75 जिलों में 150 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल विकसित कर रहा है, साथ ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त 75 मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल भी विकसित किए जा रहे हैं। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों में स्मार्ट कक्षाएं और आईसीटी प्रयोगशालाएं शामिल हैं, जबकि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 1.32 लाख सरकारी स्कूलों को सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। डिजिटल पहुंच भी इस प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत युवाओं को 49.86 लाख से अधिक टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं, जबकि इस योजना का लक्ष्य 2 करोड़ युवाओं तक पहुंचना है। किसी विद्यार्थी के लिए कोई उपकरण केवल एक उपकरण नहीं है। इसका अर्थ स्कूल के बाद ऑनलाइन पाठ्यक्रम तक पहुंच, छात्रवृत्ति या परीक्षा की जानकारी, ऐसी तैयार सामग्री तक पहुंच जो अन्यथा कठिन हो सकती है, या कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों से आगे किसी विषय को समझने का अवसर हो सकता है। इस तरह डिजिटल पहुंच केवल यह नहीं बताती कि युवा क्या सीखते हैं, बल्कि यह भी बताती है कि वे क्या सीखने की कल्पना कर सकते हैं। देश की कुछ सबसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए तैयारी के संसाधनों तक पहुंच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना UPSC, UPPSC, JEE और NEET जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराती है। 2026 तक यह योजना 163 केंद्रों के माध्यम से संचालित हो रही है और 23,000 से अधिक युवाओं को सहायता दे रही है। जिन युवाओं की आकांक्षाएं बड़ी हैं लेकिन महंगी निजी कोचिंग तक पहुंच सीमित हो सकती है, उनके लिए सरकारी सहायता से मिलने वाली तैयारी प्रतिस्पर्धी अवसर को अधिक सुलभ बना सकती है। युवा महिलाओं के लिए शिक्षा तक पहुंच का अर्थ ऐसे वातावरण का निर्माण भी है जहां सीखने के साथ आत्मविश्वास और स्वतंत्रता विकसित हो सके। राज्य में वर्तमान में 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, जिनमें कक्षा 6 से 12 तक 87,647 छात्राएं नामांकित हैं। इन विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं और आईसीटी प्रयोगशालाओं के साथ-साथ आत्मरक्षा प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने में यह समझने में मदद करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि उनका भविष्य कैसा हो सकता है। 2,306 स्कूलों में करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जबकि 1,584 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है। विद्यार्थियों को सीखने और करियर से संबंधित संसाधनों तक बेहतर पहुंच देने के लिए ई-लाइब्रेरी और करियर पोर्टल भी विकसित किए गए हैं। ये पहल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि करियर चुनना उतना ही इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति क्या संभव है, यह जानता है, जितना इस पर कि वह क्या चाहता है। यह यात्रा उच्च शिक्षा तक जारी रहती है, जहां 38 राज्य

विश्वविद्यालय, एक डीम्ड विश्वविद्यालय, एक ओपन विश्वविद्यालय और 52 निजी विश्वविद्यालय हैं, साथ ही 217 सरकारी डिग्री कॉलेज भी हैं। 71 नए सरकारी डिग्री कॉलेजों की घोषणा की गई है, जबकि RUSA के तहत 26 मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं। विस्तार के साथ-साथ शिक्षा ऋण पर ब्याज में सब्सिडी, शोधार्थियों के लिए प्रोत्साहन और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित नीतियों के प्रावधान उच्च शिक्षा के वातावरण को और मजबूत करते हैं। अंततः शिक्षा केवल एक योग्यता नहीं है। यह वह आधार है जहां से युवा यह तय करना शुरू करता है कि वह क्या बनना चाहता है।

हालांकि, केवल डिग्री ही भविष्य के काम को परिभाषित नहीं करती। आज कार्यबल में प्रवेश करने वाले युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि जिस कार्यस्थल के लिए वे तैयारी कर रहे हैं, वह स्वयं बदल रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, उन्नत कंप्यूटिंग और डिजिटल सेवाएं उद्योगों को नया आकार दे रही हैं और नियोक्ताओं द्वारा अपेक्षित कौशल को बदल रही हैं। आज जिस करियर की तैयारी कोई विद्यार्थी करता है, वह पांच वर्ष बाद उसके करियर के दौरान बहुत अलग रूप ले सकता है। यही कारण है कि कौशल विकास तेजी से महत्वपूर्ण हो रहा है। सवाल अब केवल यह नहीं है कि "आपने क्या पढ़ा?" बल्कि यह भी है कि "आप अभी क्या कर सकते हैं और आगे क्या कर पाएंगे?" उत्तर प्रदेश सरकार की कौशल विकास पहलों ने इसलिए केवल युवाओं को प्रशिक्षण देने पर ही नहीं, बल्कि उस प्रशिक्षण को रोजगार के उभरते क्षेत्रों से जोड़ने पर भी ध्यान दिया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और आईटीआई के माध्यम से 25.80 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 10.20 लाख से अधिक को बाद में रोजगार उपलब्ध कराया गया। कार्यस्थल के साथ प्रशिक्षण का स्वरूप भी बदल रहा है। पारंपरिक व्यावसायिक ट्रेडों के साथ-साथ कार्यक्रमों में इंडस्ट्री 4.0 से जुड़े क्षेत्रों, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स शामिल हैं, को भी शामिल किया जा रहा है। तकनीक पर राज्य का जोर उत्तर प्रदेश एआई मिशन और रोबोटिक्स मिशन के माध्यम से भी दिखाई देता है। एआई मिशन के तहत 49 आईटीआई में एआई लैब स्थापित की जा रही हैं, साथ ही एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इंडिया एआई डेटा लैब्स की दिशा में काम हो रहा है। युवाओं और सरकारी कर्मियों दोनों के लिए साइबर सुरक्षा से जुड़े प्रयास भी किए जा रहे हैं। एक युवा के लिए इन विकासों का अर्थ ऐसे करियर में प्रवेश करने की संभावना है जो पारंपरिक विकल्पों का हिस्सा नहीं रहे होंगे,जैसे इंजीनियर, तकनीशियन, शोधकर्ता और प्रोग्रामर ही नहीं, बल्कि डिजाइनर, ऑपरेटर, डिजिटल प्रोफेशनल और उद्यमी भी। प्रस्तावित मुख्यमंत्री डिजिटल एंटरप्रेन्योर योजना इस विचार को आगे बढ़ाती है। इसका उद्देश्य प्रत्येक न्याय पंचायत में एक डिजिटल उद्यमी विकसित करना है, जिसके लिए चयनित युवाओं को उपकरण, प्रशिक्षण और ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाएगा, इनमें 50 प्रतिशत चयन महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। लक्ष्य केवल युवाओं को रोजगार योग्य बनाना नहीं है। लक्ष्य उन्हें अनुकूल बनाना और उनके आसपास की दुनिया बदलने के साथ लगातार सीखते रहने में सक्षम बनाना है।



मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना UPSC, UPPSC, JEE और NEET जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराती है। 2026 तक यह योजना 163 केंद्रों के माध्यम से संचालित हो रही है और 23,000 से अधिक युवाओं को सहायता दे रही है। जिन युवाओं की आकांक्षाएं बड़ी हैं लेकिन महंगी निजी कोचिंग तक पहुंच सीमित हो सकती है, उनके लिए सरकारी सहायता से मिलने वाली तैयारी प्रतिस्पर्धी अवसर को अधिक सुलभ बना सकती है। युवा महिलाओं के लिए शिक्षा तक पहुंच का अर्थ ऐसे वातावरण का निर्माण भी है जहां सीखने के साथ आत्मविश्वास और स्वतंत्रता विकसित हो सके। राज्य में वर्तमान में 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, जिनमें कक्षा 6 से 12 तक 87,647 छात्राएं नामांकित हैं। इन विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं और आईसीटी प्रयोगशालाओं के साथ–साथ आत्मरक्षा प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

जब शिक्षा और कौशल अवसर का द्वार खोल देते हैं, तो अगला सवाल कई युवाओं के लिए स्वाभाविक होता है कि काम कहां से मिलेगा? उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार सृजन के लिए कई रास्तों पर काम किया है। विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से 9 लाख से अधिक युवाओं का सरकारी नौकरियों के लिए चयन हुआ है। वन–टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) जैसी व्यवस्थाएं भी शुरू की गई हैं, ताकि सरकारी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया आसान हो सके। राज्य में निवेश भी सरकारी रोजगार से आगे अवसर पैदा कर रहा है। पिछले नौ वर्षों में ₹50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों से 1.10 करोड़ से अधिक युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, जबकि जमीन पर उतर चुके ₹15 लाख करोड़ के प्रस्ताव 60 लाख रोजगार अवसरों से जुड़े हैं। इस निवेश से एक विशेष रोजगार तंत्र विकसित होने का उदाहरण उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। इस पहल में ₹34,844 करोड़ के प्रस्तावित निवेश वाले 197 समझौता ज्ञापन हुए हैं, जिनसे अनुमानित 52,658 प्रत्यक्ष रोजगार अवसर पैदा होने की संभावना है। इनमें से 62 उद्योगों को भूमि आवंटित की जा चुकी है, जिनसे अनुमानित 14,256 प्रत्यक्ष नौकरियां जुड़ी हैं, जबकि नौ औद्योगिक इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। हालांकि आज के युवाओं के लिए रोजगार का अर्थ हमेशा किसी और द्वारा बनाई गई नौकरी पाना नहीं होता। किसी विचार, कौशल, स्थानीय उत्पाद या जोखिम उठाने की इच्छा रखने वाले युवा के लिए उद्यमिता एक दूसरा रास्ता हो सकती है। इससे आर्थिक स्वतंत्रता मिल सकती है और दूसरों के लिए भी आजीविका के अवसर पैदा हो सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ऐसी ही एक पहल है, जो अपना उद्यम स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को सहायता देती है। इस योजना के तहत 37,000 से अधिक लाभार्थियों को सहायता मिल चुकी है। स्वरोजगार पर इसी तरह का जोर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) में भी दिखाई देता है, जिसके तहत 32,936 लाभार्थियों को ₹1,105 करोड़ से अधिक की मार्जिन मनी सहायता मिली है और 2.63 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। किसी विचार को कागज से उद्यम में बदलने में व्यापक ऋण व्यवस्था की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वरोजगार के इन रास्तों के साथ–साथ उत्तर प्रदेश नवाचार आधारित उद्यमिता के लिए भी वातावरण मजबूत कर रहा है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 ऐसे वातावरण के निर्माण पर अधिक जोर देती है जिसमें युवा उद्यमी नए विचारों को विकसित और बड़े स्तर पर विस्तार दे सकें, विशेष रूप से उभरते और प्रौद्योगिकी–आधारित क्षेत्रों में। यह नीति स्टार्ट–अप के लिए इनक्यूबेशन, निवेश और संस्थागत सहायता के विस्तार के राज्य के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

हालांकि, एक और कारक यह तय कर सकता है कि कोई अवसर किसी युवा को वास्तव में सुलभ महसूस होता है या नहीं, वह कहां रहता है। किसी बड़े शहर में रहने वाले युवा के लिए कोई पाठ्यक्रम, बाजार, प्रशिक्षण केंद्र या पेशेवर नेटवर्क अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध हो सकता है। लेकिन ग्रामीण या अर्ध–शहरी क्षेत्र के युवा के लिए वही

अवसर दूरी, कनेक्टिविटी या जानकारी तक सीमित पहुंच के कारण दूर हो सकता है। इसलिए अवसरों का विस्तार करने का अर्थ उन्हें युवाओं के घर के करीब लाना भी है। प्रोजेक्ट गंगा के माध्यम से राज्य 20 लाख ग्रामीण और अर्ध–शहरी परिवारों को हाई–स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। बड़े शहरों से बाहर रहने वाले युवाओं के लिए विश्वसनीय कनेक्टिविटी का अर्थ ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल सेवाओं, रोजगार और उद्यमिता की जानकारी तथा अपने आसपास के बाजारों से कहीं आगे तक पहुंच हो सकता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल अवसर के सवाल को एक अलग दिशा से देखती है। इसका उद्देश्य युवाओं को अवसर की तलाश में अपने जिले से बाहर जाने के लिए मजबूर करने के बजाय उन कौशलों, उत्पादों और आर्थिक ताकतों के आसपास अवसर तैयार करना है जो पहले से उनके क्षेत्र में मौजूद हैं। ODOP से जुड़े कौशल विकास के तहत 1.46 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है या टूलकिट उपलब्ध कराई गई है, जबकि योजना के तहत हजारों लाभार्थियों को वित्तीय सहायता मिली है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना भी पारंपरिक कौशलों को आधुनिक सहायता से जोड़ती है, इसके तहत 4.20 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षण और आधुनिक टूलकिट के माध्यम से सहायता दी गई है। इसके साथ ही ODOP ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मेलों में भागीदारी के लिए सहायता जैसी पहलें स्थानीय उत्पादों को उनके तत्काल बाजारों से आगे ले जाने का प्रयास करती हैं। युवाओं के लिए यह महत्वाकांक्षा को देखने का एक और तरीका प्रस्तुत करता है। भविष्य बनाना जरूरी नहीं कि अपना जिला छोड़ना ही हो। पारंपरिक और ग्रामोद्योगों पर व्यापक ध्यान भी इसी विचार को मजबूत करता है। खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र की पहलों ने 2017–18 से 2024–25 के बीच 4.63 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा किया है, जबकि 2026–27 के लिए 30,000 और रोजगार अवसरों का लक्ष्य रखा गया है। तकनीक इन पारंपरिक आजीविकाओं में भी जगह बना रही है। सोलर चरखों जैसी पहलों के समर्थन से 4,677 लाभार्थियों को सोलर चरखे मिले हैं, जिससे 9,354 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

कई युवाओं के लिए हालांकि उनका जुनून खेल के मैदान में होता है। खेल केवल रुचि नहीं, बल्कि एक युवा खिलाड़ी के लिए संभावित करियर भी हो सकता है। ऐसा





करियर जिसके लिए प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा, उपकरण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर जरूरी हैं। इसे ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में खेलों के तंत्र को मजबूत करने में निवेश किया है। सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना है, साथ ही वन मंडल–वन स्पोर्ट्स कॉलेज की पहल भी है। राज्य ने एक जनपद, एक खेल पहल भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में एक विशेष खेल की पहचान और विकास करना तथा स्थानीय स्तर पर खेल के अवसरों को अधिक सुलभ बनाना है। जिला स्तर पर विकास का यह जोर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। प्रतिभा केवल स्थापित खेल केंद्रों में ही नहीं उभरती और किसी युवा खिलाड़ी की क्षमता केवल किसी बड़े शहर तक पहुंच पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। एक जनपद, एक खेल के तहत सभी 75 जिलों में प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जबकि युवा खिलाड़ियों को सहयोग देने के लिए खेल उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी रोजगार का प्रावधान भी है। एक युवा खिलाड़ी के लिए ये पहलें खेल को शिक्षा के साथ–साथ की जाने वाली गतिविधि से एक ऐसे भविष्य के रास्ते में बदलने में मदद कर सकती हैं जिसे गंभीरता से अपनाया जा सके। आखिरकार, अवसर का अर्थ यही हैरू पहले से यह तय न करना कि कौन–सी महत्वाकांक्षाएं महत्वपूर्ण हैं, बल्कि अलग–अलग प्रकार की प्रतिभाओं को अपना स्थान खोजने के लिए पर्याप्त रास्ते उपलब्ध कराना।

उत्तर प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं का कोई एक तय प्रारूप नहीं है। कोई युवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो सकता है। कोई आईटीआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहा हो सकता है। कोई अपने परिवार की पारंपरिक कला या शिल्प को ऑनलाइन व्यवसाय में बदलने की कोशिश कर रहा हो सकता है। उनकी महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल अलग हो सकती हैं, लेकिन उनमें एक बात समान है, उन्हें अवसर, पहुंच और अपनी दिशा चुनने की स्वतंत्रता चाहिए। कक्षा से कार्यस्थल तक, पारंपरिक शिल्प से उभरती तकनीकों तक और स्थानीय उद्यमों से खेल के मैदान तक, सरकार की पहलें युवाओं को राज्य की विकास यात्रा के केंद्र के और करीब लाने के निरंतर प्रयास को दर्शाती हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उत्तर प्रदेश के युवाओं की विविधता और उन अनेक रूपों को पहचानती हैं जिनमें उनकी प्रतिभा राज्य के विकास में योगदान दे सकती है। आने वाले वर्ष नई चुनौतियां और नई संभावनाएं लेकर आएंगे, लेकिन युवा आबादी, बढ़ते अवसरों और उसकी क्षमता को सक्षम बनाने पर केंद्रित नीतिगत दृष्टिकोण के साथ उत्तर प्रदेश अपने युवाओं को विकास का सबसे मजबूत आधार बनाने की दिशा में अच्छी स्थिति में है। उत्तर प्रदेश का भविष्य उसके युवाओं का है और आज उनकी क्षमता में निवेश करके राज्य कल के उत्तर प्रदेश की नींव तैयार कर रहा है।

(लेखक मैके. इंजी. एवं स्वतंत्र पत्रकार हैं)
मो. : 8879989437

उत्तर प्रदेश देश में नंबर – 1

–अजय मिश्रा

भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ की वर्तमान आबादी तकरीबन 147 करोड़ है। ऐसे में देश का विकास राज्यों के विकास पर निर्भर होना स्वाभाविक है। आंतरिक संरचना और राज्यों के क्रियाकलापों में राजनीतिक भिन्नता भी राज्य की तरक्की में कई बार बाधक बन जाती है, जबकि देश के विकास के लिए सभी राज्य रूपी पहियों का समान गति से चलना आवश्यक है।

एक तरफ जहाँ जनसंख्या के अनुपात में सुविधाएं और शांति बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, वहीं दूसरी तरफ विकास के लिए लगातार कार्य, कड़ी मेहनत और समयानुसार त्वरित निर्णय की आवश्यकता होना स्वाभाविक है। ऐसे में एक तरफ जहाँ केंद्र सरकार देश की प्रगति की रफ्तार को बढ़ाने में लगी है, वहीं राज्यों की एक–एक क्रियाविधि का भी इस तरक्की में महत्वपूर्ण स्थान है।



उत्तर प्रदेश आबादी में देश का सबसे बड़ा राज्य है। वर्ष 2017 के पूर्व के शासनकाल में वह कई चुनौतियों से न केवल लड़ रहा था, बल्कि उसकी राष्ट्रीय छवि भी अनेक अनुचित वजहों से जानी जाती थी और यदि हम अब शासन और सत्ता के दावों को खारिज करके भी उत्तर प्रदेश में हुए बड़े बदलाव को महसूस करें, तो स्वतः आवाज निकलती है कि इस उपलब्धि के पीछे निःस्वार्थ भाव से की गई कड़ी मेहनत और सच्ची ईमानदारी से किया जा रहा कार्य ही प्रभावशाली रूप में सामने आया है। यह संभव हो पाया है तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के समर्पण और आम जन के हितों के लिए लगातार कार्य करने तथा निर्णय लेने की दृढ़ क्षमता से।

आज एक–दो नहीं, बल्कि अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जो यह स्वतः साबित करते हैं कि उत्तर प्रदेश वैश्विक मंच पर अपनी सकारात्मक छवि बनाने में सफल हो गया है। यदि हम देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उपलब्धियों का मूल्यांकन राष्ट्रीय स्तर पर करें, तो उत्तर प्रदेश एक अनूठा और उत्कृष्ट स्थान बना चुका है और दूरदर्शिता वाला यह नेतृत्व भविष्य में वैश्विक स्तर की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उत्तर प्रदेश का देश में कई बातों और रैंकिंग में प्रथम होना यह दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ और उनकी कोर टीम ने जनता के हित में लगातार कार्य किया है। आज प्रदेश में चारों तरफ एक–दो नहीं, बल्कि ऐसी अनेक उपलब्धियाँ दिखाई पड़ रही हैं, जो स्वतः सरकार के सकारात्मक उद्देश्यों की गवाही दे रही हैं।

यदि देखा जाए तो दुनिया भर में चीन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और नाइजीरिया जैसे देशों को छोड़कर सर्वाधिक आबादी उत्तर प्रदेश की है । ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम होना सच्ची और ईमानदारीपूर्ण क्रियाविधि को दर्शाता है। ये उपलब्धियाँ प्रदेश को देश में न केवल प्रथम स्थापित कर रही हैं, बल्कि सफलता की एक मजबूत इमारत का निर्माण भी कर रही हैं।

यह उपलब्धियाँ हैं :–

- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड सुनिश्चित करने में देश में प्रथम स्थान।
- इथेनॉल उत्पादन और आपूर्ति में देश में प्रथम स्थान।
- एक महा अभियान के तहत वर्ष 2025 में राज्य में 37.21 करोड़ पौधरोपण का रिकॉर्ड।
- 96 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग स्थापित करके देश में प्रथम।



- धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में प्रथम स्थान।
- प्रदेश को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में देश में पहला स्थान प्राप्त।
- क्रेता–विक्रेता गौरव सम्मान समारोह 2023 में राज्य को छह श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।
- व्यापार सुगमता में प्रदेश एक अग्रणी राज्य है।
- उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में लगातार देश में प्रथम स्थान पर है, जहाँ वर्ष 2023–24 में 177 मिलियन टन गन्ना उत्पादन, वर्ष 2024–25 में लगभग 4.2 मिलियन टन शीरा तथा वर्ष 2024–25 में लगभग 91.1 लाख टन (9.11 मिलियन टन) चीनी का उत्पादन हुआ।
- उत्तर प्रदेश ई–मार्केट प्लेस (GeM) के तहत सबसे अधिक सरकारी खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने वर्ष 2024–25 में GeM के माध्यम से कुल 5.43 लाख करोड़ रुपये के 72 लाख से अधिक खरीद ऑर्डर निष्पादित किए हैं।
- वर्ष 2023–24 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार दिया गया।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना तैयार करने में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी है।
- कौशल विकास नीति को लागू करने वाला यूपी पहला राज्य है और (एनपीएस) के अंतर्गत श्रमिकों का पंजीकरण करने में देश में प्रथम स्थान पर है।
- भारत स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता–2022 में विभिन्न श्रेणियों में कुल 10 पुरस्कार प्राप्त हुए।
- नौवें स्मार्ट सिटी एक्सपो में कानपुर को पालिका स्पोर्ट्स स्टेडियम के आधुनिकीकरण और विकास कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ विरासत एवं ऐतिहासिक वास्तुकला तथा लैंडमार्क प्रस्तुति पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) के अंतर्गत 58 लाख से अधिक आवासों के निर्माण में देश में प्रथम स्थान।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कार्यान्वयन में देश में प्रथम। लगभग 2.86 करोड़

किसानों को 80,000 करोड़ रुपये से अधिक वितरित।

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.85 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान कर यूपी देश में प्रथम।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी–पटरी वालों को लगभग 20 लाख ऋण वितरित करके देश में प्रथम।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 2.68 करोड़ स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करके देश में प्रथम।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 9.57 करोड़ खातों के साथ देश में प्रथम।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 6.52 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में अव्वल।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2.28 करोड़ नामांकन के साथ देश में प्रथम।
- अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1.12 करोड़ से अधिक नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
- अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव में लगातार कई वर्षों से दीप प्रज्वलित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लगातार नाम दर्ज हो रहा है।
- उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मेट्रो का कार्य और मेट्रो के विस्तार का कार्य का होना।



राजनीतिक चश्मे को उतारकर देखने पर या बिना पक्षपात के इन उपलब्धियों का मूल्यांकन करने पर आपको स्वतः ही इसके पीछे किए गए कठिन कार्य और योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता तथा प्रत्येक प्रदेशवासी को मजबूत बनाने की दृढ़ इच्छाशक्ति महसूस होगी।

इन उपलब्धियों के अलावा अनेक ऐसी उपलब्धियाँ हैं, जिससे आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर है। यदि आम जन की जमीनी आवश्यकताओं की बात की जाए, तो आज रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और सुरक्षा सरकार प्रत्येक नागरिक के दरवाजे तक लेकर खड़ी है।

आवास आज प्रदेश के कोने–कोने में लोगों को मिल रहा है, राशन सभी को प्राप्त हो रहा है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सड़क की सुविधा घर–घर पहुँची है। इन सबके साथ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु "सुरक्षा" है, जो कुछ वर्षों पहले कागजों तक सीमित थी, उसे आम आदमी तक पहुँचाने का कार्य इस सरकार ने किया है।

तभी तो आज लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करके सरकार एक नया इतिहास रचने का कार्य भी कर रही है।

उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम बनाना, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कठिन परिश्रम का प्रमाण है, और आने वाले समय में प्रदेश को अनेक लाभ एवं उपलब्धियों के साथ विकसित प्रदेश का मजबूत ढांचा सभी को दिखाई देने वाला है। ◆

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

मो. : 9335226715



आत्मनिर्भर युवा विकसित यूपी का मजबूत आधार

–आदर अदीब पावेल बन्धु

युवा केवल किसी राष्ट्र की जनसंख्या का एक वर्ग नहीं, बल्कि उसके उज्ज्वल भविष्य की सबसे अमूल्य पूंजी होते हैं। जब उनके हाथों में कौशल, मन में आत्मविश्वास और सामने अवसरों का विस्तृत आकाश होता है, तब विकास का नया इतिहास रचा जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इसी विचार को आधार बनाकर कौशल विकास को जनांदोलन का स्वरूप दिया है। आज उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन लाखों युवाओं के सपनों को साकार करने वाला ऐसा सशक्त सेतु बन चुका है, जो उन्हें आत्मनिर्भरता, सम्मानजनक आजीविका और राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ रहा है।

भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लिए कौशल विकास केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता का सबसे सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को अधिक प्रभावी, आधुनिक और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। आज कौशल विकास मिशन लाखों युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ते हुए प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था तथा विकसित भारत–2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर कर रहा है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का गठन उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति–2013 के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन किया गया। मिशन का उद्देश्य 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को उनकी योग्यता और रुचि के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। मिशन के अंतर्गत राज्य स्किल डेवलपमेंट फंड (SSDF), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप प्रोजेक्ट प्रवीण जैसी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से विद्यालयों के विद्यार्थियों को नियमित पाठ्यक्रम के साथ निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे शिक्षा के साथ–साथ रोजगारपरक दक्षता भी विकसित हो रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन ने अभूतपूर्व उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। मिशन की स्थापना से अब तक 18 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण

प्रदान किया जा चुका है, जबकि 7 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि प्रदेश सरकार कौशल विकास को सीधे रोजगार और आर्थिक सशक्तीकरण से जोड़ने में सफल रही है।

रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है। अब तक 1,194 बृहद रोजगार मेलों के माध्यम से 4,52,976 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इनमें 8 जनपदों में आयोजित 8 वृहद रोजगार मेलों के माध्यम से 75,675 युवाओं को रोजगार मिला। इसके अतिरिक्त विश्व युवा कौशल दिवस (15 जुलाई) के अवसर पर प्रदेश के 75 जनपदों में आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से 10,283 युवाओं का सेवायोजन किया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

प्रदेश सरकार ने कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग किया है। प्रशिक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए 'कौशल दर्पण', 'कौशल दिशा', 'कौशल साथी' तथा 'कौशल दोस्त' जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं। इन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन, प्रशिक्षण, निगरानी, मूल्यांकन तथा रोजगार संबंधी सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही प्रशिक्षण केंद्रों और प्रशिक्षणार्थियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग से पूरी व्यवस्था अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनी है।

उद्योगों की बदलती आवश्यकताओं













को देखते हुए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निरंतर सुधार किया है। नई तकनीकों, डिजिटल स्किल, ग्रीन एनर्जी, स्वास्थ्य सेवाओं तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 82 नए प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर (PTPs) को मिशन से संबद्ध किया गया है। इससे युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध हो रहा है।

राज्य सरकार ने उद्योग और कौशल विकास के बीच मजबूत समन्वय स्थापित किया है। प्रदेश की 53 बड़ी औद्योगिक कंपनियों के साथ मिशन के समझौते किए गए हैं, जिससे प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। यह पहल 'स्किल टू एम्प्लॉयमेंट' मॉडल को सफल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने के लिए मिशन ने प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ भी साझेदारी की है। उच्च तकनीकी प्रशिक्षण हेतु IIT कानपुर, MNNIT प्रयागराज, IIT BHU, NIESBUD तथा भारतेन्दु नाट्य अकादमी जैसे संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित किया गया है। वहीं सॉफ्ट स्किल, वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता विकास के लिए 7 संस्थानों के साथ एमओयू किए गए हैं। इससे युवाओं को तकनीकी ज्ञान के साथ व्यक्तित्व विकास और उद्यमिता का प्रशिक्षण भी प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0 के माध्यम से 1,182 दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार निराश्रित महिलाओं, अनुसूचित जाति–जनजाति, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं को भी विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार आधुनिक तकनीकों के अनुरूप युवाओं को तैयार करने पर विशेष बल दे रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV), ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थकेयर, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, आतिथ्य, परिधान निर्माण और अन्य आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है। इससे प्रदेश के युवा भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष बन रहे हैं।

नवभारत के निर्माण की नई दिशा

उत्तर प्रदेश ने कौशल विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बनाई है। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता–2026 के लिए प्रदेश से 1,09,249 युवाओं का पंजीकरण हुआ, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। यह उपलब्धि बताती है कि प्रदेश के युवाओं में तकनीकी दक्षता और नवाचार की क्षमता निरंतर बढ़ रही है।



आगामी वर्षों के लिए भी प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वर्ष 2026–27 में 4 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 1 जुलाई 2026 तक 2 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य निर्धारित किया गया था। साथ ही 1M1B जैसी संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न तकनीकी एवं फ्यूचरिस्टिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है। अंत्योदय परिवारों, दिव्यांगजनों तथा वंचित वर्गों के युवाओं को विशेष प्राथमिकता देते हुए कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है। निजी आईटीआई एवं अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ साझेदारी भी लगातार बढ़ाई जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने यह सिद्ध कर दिया है कि कौशल ही आत्मनिर्भरता का सबसे मजबूत आधार है। लाखों युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़कर मिशन ने प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति प्रदान की है। आधुनिक तकनीक, उद्योगों के साथ साझेदारी, डिजिटल नवाचार और रोजगारपरक प्रशिक्षण की बदौलत उत्तर प्रदेश आज देश के अग्रणी कौशल विकास राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है।

युवा केवल किसी राष्ट्र की जनसंख्या का एक वर्ग नहीं, बल्कि उसके उज्ज्वल भविष्य की सबसे अमूल्य पूंजी होते हैं। जब उनके हाथों में कौशल, मन में आत्मविश्वास और सामने अवसरों का विस्तृत आकाश होता है, तब विकास का नया इतिहास रचा जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इसी विचार को आधार बनाकर कौशल विकास को जनआंदोलन का स्वरूप दिया है। आज उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन लाखों युवाओं के सपनों को साकार करने वाला ऐसा सशक्त सेतु बन चुका है, जो उन्हें आत्मनिर्भरता, सम्मानजनक आजीविका और राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ रहा है।

आज उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि युवा शक्ति के उज्ज्वल भविष्य का उद्घोष है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह मिशन लाखों युवाओं के सपनों को नई दिशा, नई गति और नई पहचान प्रदान कर रहा है। कौशल से समृद्ध युवा, आत्मनिर्भर परिवार, सशक्त समाज और विकसित प्रदेश–इन्हीं चार स्तंभों पर विकसित उत्तर प्रदेश का भव्य भविष्य निर्मित हो रहा है। यह यात्रा केवल रोजगार प्राप्त करने की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान, स्वाभिमान और समृद्धि की यात्रा है। •

(लेखक लखनऊ के
जिला सूचना अधिकारी हैं)
मो. : 7310394573

मधु से मधुर होती जिन्दगी

—डॉ. सुयश नारायण मिश्रा

मधुमक्खियों की छोटी–सी दुनिया आज उत्तर प्रदेश के गांवों में बड़े बदलाव की कहानी लिख रही है। फूलों से रस जुटाकर तैयार होने वाला शहद अब केवल मिठास का स्वाद नहीं, बल्कि किसानों, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार, आमदनी और आत्मनिर्भरता का जरिया बन रहा है। कम संसाधनों से शुरू किया जा सकने वाला मधुमक्खी पालन खेती के साथ अतिरिक्त आय का अवसर देता है और मेहनत, प्रशिक्षण व अनुभव के साथ इसे एक सफल व्यवसाय में बदला जा सकता है। इस बदलाव के पीछे ग्रामीणों की मेहनत के साथ उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग का सहयोग भी महत्वपूर्ण है। विभाग द्वारा मधुमक्खी पालन से जुड़ने वाले लोगों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, टूल किट्स और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वे इस काम को केवल छोटे स्तर के प्रयास तक सीमित न रखकर व्यवस्थित स्वरोजगार के रूप में आगे बढ़ा सकें। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को बैंक ऋण और नियमानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर अपना उद्यम शुरू करने और उसका विस्तार करने का अवसर मिल रहा है। इन योजनाओं और सहयोग का असर अब गांवों की जमीन पर दिखाई देने लगा है। कहीं कुछ हनी बॉक्स से शुरू हुआ सफर सैकड़ों बॉक्स तक पहुंच गया है, तो कहीं शहद उत्पादन ने परिवार की आय बढ़ाने के साथ दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के दरवाजे खोल दिए हैं। इन सफलताओं के पीछे सिर्फ सरकारी सहायता नहीं, बल्कि उस सहायता को अवसर में बदलने वाली मेहनत, सीखने की ललक और आगे बढ़ने का संकल्प भी है। मधुमक्खियों के संग तरक्की की ये उड़ान उन ग्रामीण उद्यमियों की कहानी है, जिन्होंने छोटी शुरुआत को अपनी मेहनत से बड़ा बनाया और शहद की हर बूंद के साथ आत्मनिर्भरता की नई राह तैयार की।



उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना) भी युवाओं को उद्यम स्थापित करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं और युवाओं को अपने गांव में ही रोजगार खड़ा करने का अवसर मिल रहा है। मधुमक्खी पालन से जुड़ी सफलता की इन कहानियों में एक बात समान दिखाई देती है कि शुरुआत छोटी थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन मेहनत करने का हौसला बड़ा था। किसी ने कुछ हनी बॉक्स से सफर शुरू किया तो किसी ने प्रशिक्षण और सरकारी सहयोग के बाद अपने कारोबार का विस्तार किया। आज यही लोग शहद का उत्पादन करने के साथ–साथ दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। इनकी सफलता बताती है कि जब सरकारी योजना, सही प्रशिक्षण, स्थानीय संसाधन और मेहनत एक साथ जुड़ते हैं तो गांव में शुरू किया गया छोटा–सा काम भी आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव बन सकता है। शहद की हर बूंद में इन ग्रामीण उद्यमियों की मेहनत, संघर्ष और बदलती जिंदगी की कहानी भी घुली हुई है। बदलाव और आत्मनिर्भरता की कुछ प्रेरक कहानियां हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं उन लोगों की, जिन्होंने मधुमक्खी पालन को सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य का रास्ता बनाया।

कभी मकान बनाना सपने की तरह था

रामपुर जिले के शाहबाद क्षेत्र के ग्राम अनवा, पोस्ट टांडा निवासी वेदपाल की जिंदगी कभी बेहद सीमित संसाधनों के बीच गुजरती थी। परिवार के पास करीब एक एकड़ जमीन थी, लेकिन इतनी कम जमीन से पूरे परिवार का खर्च चलाना आसान नहीं था। कभी खेती तो कभी मजदूरी के सहारे परिवार की जरूरतें पूरी होती थीं। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि जरूरी काम भी सोच–समझकर

करने पड़ते थे। आज वही वेदपाल मधुमक्खी पालन को अपनी जिंदगी का मजबूत सहारा बना चुके हैं। करीब 100 हनी बॉक्स के साथ वह शहद का उत्पादन कर रहे हैं और उनके काम से तीन अन्य युवाओं को भी रोजगार मिला है। मधुमक्खी पालन से होने वाली आय ने न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बदली, बल्कि उन्हें अपने घर और खेती को बेहतर बनाने का अवसर भी दिया। वेदपाल ने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है। वर्ष 2012 में उन्होंने पहली बार मधुमक्खी पालन के बारे में गंभीरता से सोचा। उनके मित्र जयकिशन पहले से मधुमक्खी पालन के काम से जुड़े थे। वेदपाल उनके साथ रहने लगे, काम को करीब से देखा और मधुमक्खियों की देखभाल तथा शहद निकालने की प्रक्रिया समझी। शुरुआत में उन्होंने कुछ ही बॉक्स लेकर काम शुरू किया। काम छोटा था, लेकिन धीरे-धीरे इसमें उनकी रुचि बढ़ने लगी। वेदपाल बताते हैं कि उन्हें इस काम में अपना भविष्य दिखाई देने लगा। खेती और मजदूरी के बीच मधुमक्खी पालन उनके लिए आमदनी का एक नया रास्ता बन रहा था। इसके बाद उन्होंने खादी एवं ग्रामोद्योग से संपर्क किया। विभाग की ओर से उन्हें प्रशिक्षण और आवश्यक संसाधनों का सहयोग मिला। उन्हें निःशुल्क हनी बॉक्स और शहद निकालने की मशीन उपलब्ध कराई गई। प्रशिक्षण के दौरान रहने, खाने और सीखने की व्यवस्था भी निःशुल्क रही। वेदपाल कहते हैं, खादी ने हमें सिर्फ़ बॉक्स और मशीन नहीं दी, बल्कि काम करने का रास्ता दिखाया। अगर समय पर यह सहयोग नहीं मिलता तो शायद हम भी अपनी परिस्थितियों के कारण वहीं रह जाते। वेदपाल बताते हैं कि मधुमक्खियों के साथ काम करते-करते उन्हें इस काम से लगाव हो गया। अब मौसम के हिसाब से बॉक्स को अलग-अलग स्थानों पर ले जाना, मधुमक्खियों की देखभाल करना और सही समय पर शहद निकालना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। मधुमक्खी पालन उनके लिए सिर्फ़ शहद पैदा करने का काम नहीं रहा। यह उनके जीवन में आत्मविश्वास लौटाने का जरिया भी बन गया। आज इस काम से उनके पूरे परिवार और उनसे जुड़े अन्य लोगों का पालन हो रहा है। वह बताते हैं कि पहले उनके पास मकान की स्थिति सुधारने तक के पर्याप्त साधन नहीं थे। खेती भी सीमित संसाधनों में करनी पड़ती थी। लेकिन मधुमक्खी पालन से आमदनी बढ़ी तो उन्होंने धीरे-धीरे अपने मकान की स्थिति सुधारी और खेती में भी पहले से बेहतर निवेश किया। वेदपाल ने बताया कि वह पिछड़े वर्ग से हैं। उनके लिए आर्थिक सीमाओं से बाहर निकलना आसान नहीं था। वह कहते हैं कि अगर उन्हें सही समय पर प्रशिक्षण और सहयोग नहीं मिला होता तो शायद वह पिछले ही रह जाते। वेदपाल की कहानी यही संदेश देती है कि संसाधन कम हों तो भी सपने छोटे नहीं होने चाहिए। सही दिशा, मेहनत और समय पर मिले अवसर से छोटी शुरुआत भी बड़े बदलाव की वजह बन सकती है।

खादी एवं ग्रामोद्योग, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर का कहना है कि लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से किया जाता है। अब इसके उत्साहजनक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आने वाले समय में अतिरिक्त बजट के साथ इस योजना का और विस्तार करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।

भाई की डायरी ने दिखाई सफलता की राह

मुरादाबाद जिले के कांठ तहसील क्षेत्र के ग्राम अहमदपुर निंगु नंगला निवासी कुलदीप कुमार की कहानी इस बात की मिसाल है कि सफलता के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती। कभी गांव में छोटी-सी किराना दुकान चलाकर परिवार का खर्च निकालने की कोशिश करने वाले कुलदीप ने एक पुरानी डायरी के कुछ पन्नों में अपने लिए रोजगार की नई राह खोज ली। आज वही कुलदीप मधुमक्खी पालन और शहद के कारोबार से अपने परिवार को बेहतर जीवन देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 35 वर्षीय कुलदीप कुमार, पुत्र बृजराज सिंह, स्नातक हैं। उनका मुख्य पेशा खेती रहा है। परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं। खेती से आमदनी सीमित थी और किराना दुकान से होने वाली कमाई भी इतनी नहीं थी कि परिवार की सभी जरूरतें आसानी से पूरी हो सकें। खासकर बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च को लेकर उन्हें लगातार चिंता रहती थी। कुलदीप बताते हैं कि उनके बड़े भाई बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर चुके हैं और सरकारी नौकरी में हैं। उनके भाई की एक पुरानी डायरी थी, जिसमें मधुमक्खी पालन से जुड़ी विस्तृत जानकारी लिखी हुई थी। एक दिन कुलदीप की नजर उस डायरी पर पड़ी। उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया। मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी उन्हें रोचक लगी। इसके बाद



उन्होंने अपने बड़े भाई से इस काम के बारे में विस्तार से समझा। यहीं से उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वर्ष 2018–19 के आसपास कुलदीप ने मधुमक्खी पालन की शुरुआत की। शुरुआत छोटी थी, लेकिन उन्हें जल्दी ही महसूस हुआ कि इस काम में आगे बढ़ने की अच्छी संभावनाएं हैं। अब जरूरत थी कारोबार को विस्तार देने की और इसके लिए पूंजी की। कुलदीप ने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, मुरादाबाद से संपर्क किया। विभाग की ओर से उन्हें निःशुल्क पांच हनी बॉक्स उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में जानकारी मिली। योजना के माध्यम से उन्हें करीब पांच लाख रुपये का ऋण मिला, जिससे उन्होंने अपने काम को विस्तार देने की दिशा में कदम बढ़ाया। कुलदीप ने इस सहायता को केवल सरकारी मदद के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे अपने सपने को आगे बढ़ाने का अवसर माना। वर्तमान में उनके व्यवसाय से प्रतिवर्ष करीब 5 से 6 लाख रुपये का कारोबार हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में उनकी आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। अब वह आयकर रिटर्न यानी आईटीआर भी दाखिल करते हैं, जो उनके आर्थिक सफर में आए बदलाव को दिखाता है। कुलदीप ने अपने उत्पाद को केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कई प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया, जहां उनके शहद को सराहना मिली और उन्हें सम्मान भी प्राप्त हुआ। वह बताते हैं कि अच्छी गुणवत्ता के कारण उनके शहद को बाजार में बेचने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। कुछ शहद वह सीधे ग्राहकों को बेचते हैं, जबकि कुछ की बिक्री ट्रेडर्स के माध्यम से होती है। शहर के बाजार में उनके शहद की अच्छी मांग है। अभी उनका अपना ब्रांड नहीं है, लेकिन भविष्य में वह अपने शहद को एक ब्रांड के रूप में बाजार में उतारना चाहते हैं। मधुमक्खी पालन और शहद के कारोबार ने कुलदीप के परिवार की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां परिवार की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल होता था, वहीं अब आमदनी का बेहतर साधन उपलब्ध है।

पांच हनी बॉक्स से शुरू हुआ सफर 650 तक पहुंचा

मेहनत करने का जज्बा हो और सही समय पर अवसर मिल जाए तो छोटी–सी शुरुआत भी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। सम्भल जिले के ग्राम सेवराज सतरनगला निवासी सन्दीप कुमार की कहानी इसकी मिसाल है। कभी सीमित आमदनी और रोजगार की तलाश से जूझ रहे सन्दीप ने मधुमक्खी पालन को अपने जीवन का रास्ता बनाया और आज इसी काम से न केवल अपने परिवार की आर्थिक जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बल्कि सालाना लाखों रुपये की आय भी अर्जित कर रहे हैं। 32 वर्षीय सन्दीप कुमार, पुत्र राजेन्द्र सिंह, स्नातक हैं। उनका मुख्य व्यवसाय खेती रहा है। मधुमक्खी पालन से उनका रिश्ता नया नहीं है। उनके पिताजी ने कभी ये काम किया था लेकिन पर्याप्त जानकारी और तकनीकी प्रशिक्षण के अभाव के चलते वह इस रोजगार को बहुत आगे नहीं बढ़ा पाये। उस समय सन्दीप पढ़ाई कर रहे थे। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स किया और नौकरी शुरू कर दी। नौकरी से करीब 12 हजार रुपये मासिक मिलते थे। परिवार की जरूरतों और बढ़ते खर्च के बीच यह आय पर्याप्त नहीं थी। सन्दीप के मन में हमेशा अपना काम खड़ा करने की इच्छा बनी रही। वर्ष 2014 के आसपास उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग से संपर्क किया। विभाग की मदद से उन्हें प्रशिक्षण मिला और मधुमक्खी पालन की आधुनिक तकनीक और व्यवसाय से जुड़ी जरूरी जानकारी हासिल हुई। यही प्रशिक्षण उनके लिए निर्णायक मोड़ साबित हुआ। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग से भी उन्हें सहयोग मिला। इसके बाद उन्होंने अपने काम का विस्तार किया और एमएसएमई के तहत सब्सिडी और लोन लेकर डिब्बों की संख्या बढ़ाकर

करीब 100 कर दी। वर्ष 2016 तक उनकी आमदनी करीब चार लाख रुपये सालाना पहुंच गई। इसके बाद सन्दीप ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे–धीरे मधुमक्खी के डिब्बों की संख्या बढ़ती गई और आज उनके पास करीब 650 हनी बॉक्स हैं। अब वह केवल मधुमक्खी पालन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने शहद का प्रसंस्करण कर उसे सीधे बाजार में बेचते हैं। इससे उनकी सालाना आय करीब 10 से 11 लाख रुपये तक पहुंच गई है। आज मधुमक्खी पालन उनके लिए केवल अतिरिक्त आय का साधन नहीं, बल्कि एक सफल व्यवसाय बन चुका है। शहद के प्रसंस्करण और सीधे बाजार में बिक्री से उन्हें बेहतर आमदनी हो रही है। खेती के साथ मधुमक्खी पालन ने उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का आत्मविश्वास दिया है। सन्दीप का मानना है कि गांव के युवाओं में हुनर और मेहनत की कमी नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ सही जानकारी, प्रशिक्षण और अवसर की। वह बताते हैं कि विभाग से मिले मार्गदर्शन ने उन्हें यह समझने में मदद की कि ग्रामीण क्षेत्र में रहकर भी रोजगार का मजबूत साधन तैयार किया जा सकता है। आज सन्दीप खुद दूसरे ग्रामीण युवाओं को मधुमक्खी पालन और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी कहानी बताती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं होता। सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के साथ यही सहायता किसी व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दे सकती है। सन्दीप के पिताजी का सफर पांच डिब्बों से शुरू हुआ था। शुरुआती असफलता के बाद संदीप ने कमान संभाली और आज सैकड़ों हनी बॉक्स, अपना प्रसंस्करण और बाजार में सीधे बिक्री उनकी मेहनत की पहचान बन चुके हैं। उनकी कहानी एक सीधा संदेश देती है अवसर भले ही छोटा हो, लेकिन मेहनत, सीखने की इच्छा और संकल्प उसे बड़ी सफलता में बदल सकते हैं।

अब दूसरों का सहारा बनीं जावित्री देवी

बदायूं जिले की दातागंज तहसील के ग्राम बक्सैना निवासी जावित्री देवी के लिए मधुमक्खी पालन सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की राह बन गया है। कभी 20 हनी बॉक्स से शुरू हुआ उनका छोटा–सा प्रयास आज करीब 150 बॉक्स तक पहुंच चुका है। मेहनत, अनुभव और सरकारी योजनाओं से मिले सहयोग के बल पर जावित्री देवी ने न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि आज उनके काम से करीब 10 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिल रहा है। जावित्री देवी पत्नी श्याम लाल को मधुमक्खी पालन के काम से पहले से परिचय था। उनके पति को इस कार्य का अनुभव था। इसी अनुभव ने जावित्री देवी को अपना काम शुरू करने का हौसला दिया। उन्हें भरोसा था कि यदि मेहनत और सही दिशा के साथ काम किया जाए तो मधुमक्खी पालन को एक सफल व्यवसाय बनाया जा सकता है। जावित्री देवी को समाचार पत्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की जानकारी मिली। योजना के बारे में जानकारी मिलने के बाद उन्होंने जिला ग्रामोद्योग कार्यालय से संपर्क किया। वहां उन्हें योजना की प्रक्रिया, वित्तीय सहायता और व्यवसाय शुरू करने से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई। जावित्री देवी ने आगे बढ़ने का फैसला किया और आवश्यक प्रक्रिया पूरी की। वर्ष 2023–24 में उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 9 लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। इस वित्तीय सहायता से उन्होंने मधुमक्खी पालन के अपने व्यवसाय को व्यवस्थित रूप से शुरू किया। शुरुआत में जावित्री देवी ने 20 हनी बॉक्स लगाए। मधुमक्खियों की देखभाल, मौसम के अनुसार उनकी व्यवस्था और शहद निकालने की प्रक्रिया को उन्होंने अपने पति के अनुभव और



विभागीय प्रशिक्षण के सहारे समझा। विभाग की ओर से उन्हें 10 दिवसीय ईडीपी प्रशिक्षण भी दिया गया। इस प्रशिक्षण में उन्हें मधुमक्खी पालन के साथ–साथ व्यवसाय को संचालित करने, बाजार की जरूरतों को समझने और कारोबार को आगे बढ़ाने से जुड़ी जानकारी मिली। शुरुआत छोटी थी, लेकिन जावित्री देवी की मेहनत बड़ी थी। इसमें उनके बेटे और पति का भी पूरा सहयोग मिला। उन्होंने धीरे–धीरे अपने काम का विस्तार करना शुरू किया। हनी बॉक्स बढ़ते गए और कारोबार भी आगे बढ़ता गया। आज उनके पास करीब 200 हनी बॉक्स हैं। सरकारी योजना के माध्यम से मिले करीब 9 लाख रुपये के वित्तीय सहयोग से शुरू हुआ उनका व्यवसाय अब करीब 12 लाख रुपये साल के स्तर तक पहुंच चुका है। जावित्री देवी अब अपने कारोबार को और विस्तार देने की तैयारी में हैं। उनकी योजना अधिक हनी बॉक्स और आवश्यक मशीनरी खरीदकर उत्पादन बढ़ाने की है। वह चाहती हैं कि उनके कारोबार को ऐसी पहचान मिले, जिससे उनका उत्पाद स्थानीय बाजार से निकलकर बड़े बाजारों तक पहुंचे। जावित्री देवी की सफलता की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि उनका स्वरोजगार अब दूसरों के लिए भी रोजगार का साधन बन गया है। उनके मधुमक्खी पालन के काम से परिवार के अलावा करीब 10 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है।

मधुमक्खियों से दोस्ती ने बनाया लखपति

कानपुर के रहने वाले विपिन कुमार की शादी साल 2012 में हुई थी। साल 2021 तक उनके पास कोई स्थायी रोजगार नहीं था। ऐसे में परिवार का खर्च व जिम्मेदारियां बहुत थीं। उन्होंने मधुमक्खी पालन से स्टार्टअप की शुरुआत की। कभी सीमित साधनों के बीच अपना भविष्य संवारने की कोशिश करने वाले विपिन कुमार आज शहद उत्पादन के व्यवसाय से जुड़कर प्रतिवर्ष लगभग 5 से 6 लाख रुपये तक की आमदनी कर रहे हैं। विपिन कुमार के अनुसार मधुमक्खी पालन कृषि आधारित व्यवसाय है और इसकी सफलता काफी हद तक मौसम तथा फूलों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अनुकूल मौसम मिलने पर शहद का बेहतर उत्पादन होता है। नवंबर से फरवरी–मार्च तक का समय शहद उत्पादन के लिए महत्त्वपूर्ण माना जाता है। विपिन कुमार ने खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग से जुड़कर मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। विभाग की ओर से उन्हें हनी बॉक्स, मधुमक्खियों की देखभाल के उपकरण, नेट ड्रेस और शहद निकालने की मशीन आदि आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई। छोटे से शुरू हुआ उनका स्टार्टअप आज बहुत बड़ा हो चुका है। आज उनके पास करीब 275 हनी बॉक्स हैं। अधिक उत्पादन के लिए वे फूलों वाले क्षेत्रों, बाग–बगीचों और फूलों वाली फसलों के आसपास हनी बॉक्स रखते हैं। स्थानीय स्तर पर फूलों की उपलब्धता कम होने पर वे अपने बॉक्स को दूसरे क्षेत्रों में भी ले जाते हैं, ताकि मधुमक्खियों को पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत मिल सके। मधुमक्खी पालन से उनके साथ करीब 7 से 10 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। बड़ी संख्या में बॉक्स को संभालना, मधुमक्खियों की देखभाल करना और शहद निकालना अकेले व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए वे जरूरत के अनुसार लोगों को काम से जोड़ते हैं। विपिन कुमार बताते हैं कि मधुमक्खी पालन में सबसे बड़ी चुनौती मौसम के प्रतिकूल होने पर मधुमक्खियों को सुरक्षित रखना है। इसके लिए विशेष देखभाल करनी पड़ती है। जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी ने भी विपिन कुमार की मेहनत और लगन की सराहना की है। वैसे तो विपिन ने विभाग की खूब तारीफ की है, लेकिन उनका स्पष्ट कहना है कि सिर्फ पांच बॉक्स से परिवर्तन नहीं आता, सतत मेहनत और ईमानदारी से यह व्यवसाय आगे बढ़ता है। वह खुश हैं कि विभाग के सहयोग और प्रशिक्षण का आज उन्हें लाभ मिल रहा है। आज विपिन कुमार की सफलता यह बताती है कि यदि ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, संसाधन और सही मार्गदर्शन मिले तो मधुमक्खी पालन न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति बदल सकता है, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार का माध्यम बन सकता है।

"उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी शिशिर ने बातचीत के दौरान बताया कि मधुमक्खी पालन ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त आय का एक बेहतर साधन बनकर उभरा रहा है। खासकर किसानों के लिए यह खेती के साथ आय बढ़ाने का अच्छा विकल्प है। बड़ी संख्या में किसान खेती के साथ मधुमक्खी पालन को अपनाकर अपनी आमदनी में वृद्धि कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड का उद्देश्य इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों तक पहुंचाना है। इसके लिए योजना के विस्तार और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।"

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)
मो. : 8924856004

बदलते युवाओं की तकदीर

शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना है या और भी लोगों के लिए नौकरी बनाना?

—सुमन शेखर



उत्तर प्रदेश, आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण यहां युवाओं की संख्या भी बहुत बड़ी है। यही युवा प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हैं, लेकिन लंबे समय तक यही ताकत एक बड़ी चुनौती भी बनी रही है, हम सब इस बात से अछूते नहीं रहे। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के सीमित अवसर, उद्योगों की कमी और कौशल के अनुसार काम न मिल पाने के कारण बड़ी संख्या में युवा लगातार दूसरे राज्यों का रुख करते रहे।

मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में युवाओं के लिए रोजगार का सवाल केवल नौकरी तक सीमित नहीं हो सकता। जरूरत इस बात की है कि पढ़ाई, कौशल, रोजगार, स्वरोजगार और उद्योग को एक–दूसरे से जोड़ा जाए। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने इसी दिशा में काम करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह सोच सामने आई है कि युवा केवल नौकरी पाने वाला न बने, बल्कि अपनी योग्यता के दम पर रोजगार पाने के साथ रोजगार देने की क्षमता भी विकसित करे।

कौशल से रोजगार तक

मैंने देखा है कि इस सरकार ने रोजगार की इस पूरी कड़ी में कौशल विकास पर खास जोर दिया गया है। 'उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन' के जरिए युवाओं को उन क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने की कोशिश की जा रही है, जहां उद्योगों को लोगों की जरूरत है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक



साढ़े बारह लाख से अधिक प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार मिला है और अब तक प्रदेश में करीब सात हजार कौशल प्रशिक्षण केंद्रों का नेटवर्क बनाया गया है।

प्रशिक्षण अब केवल पारंपरिक कामों तक सीमित नहीं है। सूचना तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवाएं, निर्माण, ऑटोमोबाइल, पर्यटन और कृषि आधारित उद्योगों के साथ नए तकनीकी क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। 35 से अधिक क्षेत्रों में 1300 से ज्यादा जॉब रोल के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहां मुझे बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक बात याद आती है– "ज्ञान में किया गया निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है।" आज के समय में किसी युवा के लिए ज्ञान और कौशल वास्तव में सबसे बड़ा निवेश है। अगर उसे सही प्रशिक्षण मिलता है तो उसके सामने रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं।

प्रशिक्षण के बाद नौकरी तक पहुंच बनाना भी जरूरी है। इसी वजह से रोजगार मेलों को इससे जोड़ा गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1194 से अधिक बड़े रोजगार मेलों के जरिए साढ़े चार लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। विश्व युवा कौशल दिवस पर प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित रोजगार मेलों में एक ही दिन दस हजार से ज्यादा युवाओं का सेवायोजन हुआ। अब कोशिश केवल कौशल सिखाने तक नहीं, बल्कि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार से जोड़ने की भी है।

अलग–अलग युवाओं की अलग–अलग मंजिल

इस समय हमने देखा है, हर युवा की मंजिल नौकरी ही नहीं होती। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में विद्यार्थी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। मैंने महसूस किया है कि इन परीक्षाओं की तैयारी में सबसे बड़ी परेशानी कई बार प्रतिभा की नहीं, आर्थिक स्थिति की होती है। महंगी कोचिंग हर परिवार के लिए कहाँ संभव है!

सरकार ने इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' शुरू की। जनवरी 2021 में इसकी घोषणा हुई और 16 फरवरी, 2021 से इसका संचालन भी शुरू हो गया। आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग, विशेषज्ञ मार्गदर्शन, मॉक टेस्ट और डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। शुरुआत ऑनलाइन माध्यम से हुई, लेकिन बाद में जिला स्तर पर अध्ययन केंद्र भी बनाए गए। आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, हापुड़ और प्रयागराज जैसे जिलों में ऐसे केंद्र सक्रिय हैं। इस तरह छोटे शहरों और सामान्य परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिल सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था– "शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है।" इसका अर्थ सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है। असली शिक्षा तब है, जब युवा अपनी क्षमता को पहचानकर उसे ज्ञान, कौशल और आत्मनिर्भरता में बदल सके।

डिजिटल सुविधा अब 'जरूरत' है

कोविड के बाद शिक्षा और रोजगार की दुनिया कितनी तेजी से डिजिटल हुई है, हमने देखा है। ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल आवेदन, ई–लर्निंग और प्रतियोगी परीक्षाओं

की तैयारी के लिए मोबाइल और इंटरनेट अब केवल सुविधा नहीं रह गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना' के तहत विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने का अभियान चलाया गया। सरकारी बजट दस्तावेजों के अनुसार करीब 49 लाख 86 हजार टैबलेट और स्मार्टफोन विद्यार्थियों तक पहुंचाए जा चुके हैं।

इस योजना को केवल उपकरण बांटने की योजना कहना ठीक नहीं होगा। ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों के विद्यार्थियों के लिए यह ऑनलाइन शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और सरकारी सेवाओं तक पहुंच का माध्यम बन सकता है। आज जब रोजगार के अवसर भी डिजिटल होते जा रहे हैं, तब डिजिटल पहुंच खुद एक तरह की आर्थिक ताकत बन गई है। एक बार नेल्सन मंडेला ने कहा था– "शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका इस्तेमाल दुनिया बदलने के लिए किया जा सकता है।" आज यह बदलाव केवल किताबों से नहीं, डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है। इसलिए तकनीक तक पहुंच को शिक्षा के अवसर से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

सरकारी नौकरी के साथ अब निजी रोजगार

उत्तर प्रदेश में रोजगार की कोशिश दो दिशाओं में दिखाई देती है, सरकारी भर्ती और निजी क्षेत्र में अवसर। मेरी एक मित्र से बात हो रही थी, उसने अभी अभी अपनी नौकरी छोड़ी थी। मैंने उससे पूछा– "अब क्या!" उसने कहा– "अब खुद की नौकरी बनानी है, अब तो और आसान है। अब भी नहीं किया तो कब करेंगे!" बात मुझे सही लगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2017 के बाद से लाखों सरकारी पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। पुलिस विभाग में ही दो लाख 19 हजार से अधिक पदों पर भर्ती का दावा किया गया है। शिक्षकों और दूसरे विभागों में भी नियुक्तियां हुई हैं।

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए केवल पदों की संख्या ही महत्वपूर्ण नहीं होती। भर्ती कब निकलेगी, परीक्षा कब होगी और प्रक्रिया कितनी पारदर्शी होगी–ये सवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए 'मिशन रोजगार' के तहत रोजगार मेलों, उद्योगों और कौशल प्रशिक्षण को साथ लाने की कोशिश हुई है। लखनऊ सहित कई शहरों में मेगा जॉब फेयर आयोजित किए गए, जहां हजारों युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में रोजगार की असली तस्वीर केवल सरकारी नौकरियों से नहीं बनेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन और थ्री–डी प्रिंटिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण शुरू होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि युवाओं को आने वाली अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करना जरूरी है।

नौकरी खोजने से नौकरी देने तक का वादा

इतने बड़े राज्य में केवल सरकारी और निजी नौकरियां रोजगार की पूरी समस्या हल नहीं कर सकतीं। इसलिए स्वरोजगार और उद्यमिता को भी महत्व देना जरूरी है। राज्य सरकार 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान'





के जरिए शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने हर साल एक लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' जैसी योजनाएं भी इसी सोच को आगे बढ़ाती हैं। यह बदलाव मुझे महत्वपूर्ण लगता है। जब कोई युवा अपना छोटा व्यवसाय शुरू करता है और उसमें दूसरे लोगों को काम देता है, तो उसका फायदा सिर्फ उसके परिवार तक सीमित नहीं रहता। उसका असर आसपास के लोगों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है।

इसी तरह 'एक जिला एक उत्पाद' योजना स्थानीय हुनर को बाजार से जोड़ने की कोशिश करती है। किसी जिले की पारंपरिक कला, शिल्प या उत्पाद को बेहतर डिजाइन, पैकेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वित्तीय सहायता और बड़े बाजार से जोड़ दिया जाए तो वही स्थानीय काम युवाओं के लिए रोजगार का माध्यम बन सकता है। इस रास्ते पर चलते हुए अब युवा केवल कमाई नहीं करता, बल्कि कुछ नया बनाने की कोशिश भी करता है।

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में युवाओं के लिए रोजगार का सवाल केवल नौकरी तक सीमित नहीं हो सकता। जरूरत इस बात की है कि पढ़ाई, कौशल, रोजगार, स्वरोजगार और उद्योग को एक-दूसरे से जोड़ा जाए। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने इसी दिशा में काम करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह सोच सामने आई है कि युवा केवल नौकरी पाने वाला न बने, बल्कि अपनी योग्यता के दम पर रोजगार पाने के साथ रोजगार देने की क्षमता भी विकसित करे।

बड़े निवेश से बड़ी उम्मीदें

खुद का रोजगार पैदा करने के लिए इसमें निवेश भी जरूरी है। रक्षा औद्योगिक गलियारा, एक्सप्रेसवे, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, सेमीकंडक्टर उद्योग और जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसी परियोजनाओं को भविष्य के रोजगार अवसरों से जोड़ा गया है।

मैंने जाना है कि किसी बड़ी परियोजना का फायदा सिर्फ उसी जगह तक सीमित नहीं रहता जहां वह बन रही होती है। उसके आसपास परिवहन, लॉजिस्टिक्स, होटल, सुरक्षा, निर्माण और तकनीकी सेवाओं में भी काम बढ़ सकता है। जैसे किसी खाली जगह पर जब कोई फैक्ट्री बनती है, वहाँ आसपास के लोगों को अबसे ज्यादा काम मिलता है। अमेरिका का पड़ोसी मेक्सिको, जब वहाँ अमेरिका ने रोजगार के लिए फैक्ट्री डाला, पूरा का पूरा रोजगार मैक्सिको के लोगों को मिला, इससे मैक्सिको आज अपनी अलग पहचान बना पाया। लोग शिक्षित हुए, रोजगार मिला, घर मिला, अच्छी परवरिश मिली। लोगों ने अब नौकरी करते खुद का काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहां सावधानी भी जरूरी है। किसी परियोजना की घोषणा और उससे पैदा होने वाली वास्तविक नौकरियों के बीच अंतर हो सकता है। इसलिए इन परियोजनाओं की सफलता का फैसला अंततः इस बात से होना चाहिए कि कितना वास्तविक निवेश आया, कितना उत्पादन हुआ और कितने लोगों को टिकाऊ रोजगार मिला।

गांव का युवा पीछे क्यों रहे

हम जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी गांवों में रहती है। इसलिए अगर रोजगार के अवसर सिर्फ लखनऊ, नोएडा या दूसरे बड़े शहरों तक सीमित रहेंगे, तो प्रदेश के हर युवा को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सरकार ने जिला स्तर पर रोजगार मेले, कृषि आधारित उद्योग, स्वरोजगार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि युवा केवल मजबूरी में दूसरे राज्यों की ओर न जाए। यहां मुझे लगता है कि पलायन को सिर्फ एक योजना से नहीं रोका जा सकता। स्थानीय स्तर पर और रोजगार बढ़ाना जरूरी है, लेकिन युवाओं को नए अवसरों के लिए खुद को तैयार करना और अपनी जिम्मेदारी निभाना और ऊर्जावान रहना भी उतना ही जरूरी है।

'मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम' के जरिए युवाओं को आकांक्षी विकास खंडों में प्रशासन के साथ काम करने का अवसर दिया जा रहा है। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं, स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों को करीब से समझने का मौका मिलता है। गांवों में युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए भी प्रयास हुए हैं। करीब 90 हजार मंगल दलों को खेल सामग्री उपलब्ध कराने की पहल इसी दिशा में है। खेल अनुशासन, टीम भावना और आगे बढ़ने का माध्यम भी बन सकते हैं।

शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी

'युवा नीति' की सबसे बड़ी परीक्षा शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी कम करने में है। सिर्फ कॉलेजों में दाखिला बढ़ा देना पर्याप्त नहीं है। पढ़ाई के साथ कौशल, अप्रेंटिसशिप, तकनीकी प्रशिक्षण और उद्यमिता का अनुभव भी जरूरी है। जॉन डेवी का विचार इस बात को बहुत अच्छी तरह समझाता है– "शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा स्वयं जीवन है।" अगर शिक्षा का संबंध जीवन और काम की वास्तविक जरूरतों से नहीं होगा, तो डिग्री और रोजगार के बीच की दूरी बनी रहेगी।

'मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना' के तहत स्नातक और डिप्लोमा धारकों को औद्योगिक संस्थानों में अप्रेंटिसशिप से जोड़ने की कोशिश इसी दिशा में है। इससे विद्यार्थियों को नौकरी शुरू करने से पहले उद्योग के वास्तविक माहौल को समझने का अवसर मिल सकता है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को अगले दशक में 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य भी रखा गया है। यह बड़ा लक्ष्य है। इसकी सफलता इस





बात पर निर्भर करेगी कि उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता कैसी रहती है, उनकी संख्या कितनी बढ़ती है और सामान्य परिवारों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा कितनी सुलभ रहती है।

असली परीक्षा अभी बाकी है

इन तमाम योजनाओं और आंकड़ों के बीच मुझे लगता है एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, किसी भी योजना की सफलता सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया या कितने लोगों को प्रमाणपत्र मिला। असल सवाल यह है कि प्रशिक्षण लेने के बाद कितने युवाओं को स्थायी और सम्मानजनक वेतन वाला रोजगार मिला? कितने युवा लंबे समय तक अपना कारोबार चला पाए? कितनी नौकरियां वास्तव में पैदा हुईं? ग्रामीण और शहरी युवाओं के बीच अवसरों का अंतर कितना कम हुआ?

इन सवालों के जवाब के लिए सरकारी आंकड़ों के साथ स्वतंत्र रोजगार सर्वेक्षण और आर्थिक अध्ययन भी जरूरी हैं। नौकरी की गुणवत्ता, वेतन, स्थिरता और क्षेत्रीय असमानता पर लगातार नजर रखनी होगी। मेरी नजर में उत्तर प्रदेश ने युवाओं को लेकर एक दिशा जरूर पकड़ी है। कौशल विकास से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, डिजिटल शिक्षा से लेकर सरकारी भर्ती, निजी रोजगार से लेकर स्वरोजगार और बड़े निवेश से लेकर ग्रामीण उद्यमिता तक कई स्तरों पर काम दिखाई देता है।

लेकिन मंजिल अभी बाकी है। इतने बड़े राज्य में हर युवा तक अवसर पहुंचाना आसान नहीं है। योजनाओं की घोषणा से ज्यादा जरूरी उनका सही क्रियान्वयन और परिणामों की ईमानदार समीक्षा है। फिर भी, आज उत्तर प्रदेश में युवाओं को केवल नौकरी की तलाश में खड़े लोगों के रूप में देखने के बजाय उन्हें कौशल, तकनीक, उद्यम और नए अवसरों से जोड़ने की कोशिश दिखाई देती है। अगर यह प्रयास जमीन पर लगातार और मजबूत होता गया, तो आने वाले वर्षों में प्रदेश का युवा केवल अपने परिवार की तकदीर नहीं बदलेगा, बल्कि अपने गांव, शहर और पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था की तस्वीर भी बदल सकता है। ◆

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)
मो. : 8877225078



यूपी में सुशासन और विकास का नया अध्याय

–उपेन्द्र कुमार

किसी भी राज्य या राष्ट्र की प्रगति, समृद्धि और नागरिकों का कल्याण उसकी सुदृढ़ कानून–व्यवस्था पर निर्भर करता है। वर्ष 2017 से पहले, देश की सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की पहचान अक्सर कानून–व्यवस्था की शिथिलता, संगठित अपराध और प्रशासनिक अकर्मण्यता के रूप में की जाती थी। भय और असुरक्षा के माहौल के कारण न केवल आम नागरिक त्रस्त था, बल्कि उद्योग और निवेश भी राज्य से दूर भाग रहे थे।

वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के साथ ही उत्तर प्रदेश में एक अभूतपूर्व प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री ने 'अपराध और अपराधियों के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति' (Zero Tolerance Policy) को शासन का मूल मंत्र बनाया।



पिछले नौ वर्षों में सरकार के कड़े फैसलों, आधुनिक तकनीकों के समन्वय और पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाकर उत्तर प्रदेश ने देश के समक्ष सुदृढ़ कानून–व्यवस्था का एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसे आज देश भर में 'यूपी मॉडल' के नाम से जाना जाता है।

उत्तर प्रदेश की कानून–व्यवस्था में सुधार केवल प्रशासनिक फेरबदल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके लिए धरातल पर कड़े और दूरगामी कदम उठाए गए। योगी सरकार ने राज्य में पैर पसार चुके पेशेवर अपराधियों और माफिया तंत्र की कमर तोड़ने का काम किया है। यूपीकोका जैसे कड़े कानूनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए चिन्हित माफियाओं और उनके सहयोगियों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की गई। अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई अरबों रुपये की संपत्तियों को कुर्क (Seize) किया गया और अवैध निर्माणों पर विधिक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस कदम ने अपराधियों के भीतर कानून का खौफ पैदा किया और आम जनता में सुरक्षा की भावना को पुनः स्थापित किया।



एक समय में उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक और क्षेत्रीय दंगों के लिए संवेदनशील माना जाता था। परंतु पिछले कुछ वर्षों में राज्य में एक भी बड़ा दंगा दर्ज नहीं हुआ है। सरकार ने उपद्रवियों और दंगा भड़काने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से ही उसकी वसूली करने का ऐतिहासिक कानून बनाकर सरकार ने अराजक तत्वों को कड़ा संदेश दिया। आज प्रदेश के सभी प्रमुख त्योहार, पर्व और धार्मिक आयोजन पूर्ण शांति, सौहार्द और सुरक्षा के माहौल में संपन्न हो रहे हैं। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा योगी आदित्यनाथ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रही है। इसके लिए राज्य व्यापी 'मिशन शक्ति' अभियान की शुरुआत की गई। महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी और अभद्रता को रोकने के लिए प्रत्येक थाने स्तर पर विशेष दस्तों का गठन किया गया।

प्रदेश के सभी थानों में समर्पित महिला हेल्प डेस्क और प्रमुख चौराहों पर 'पिंक बूथ' स्थापित किए गए, ताकि महिलाएं बिना किसी झिझक के अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। महिला अपराधों से जुड़े मामलों में पुलिस द्वारा समयबद्ध विवेचना (Investigation) और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अपराधियों को रिकॉर्ड समय में सजा दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

कानून–व्यवस्था को केवल सख्त आदेशों से नहीं, बल्कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण और उन्हें साधन–संपन्न बनाकर दीर्घकालिक रूप से सुदृढ़ किया गया है। सरकार ने पुलिस विभाग में खाली पड़े लाखों पदों पर पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से भर्तियां कीं। बड़े पैमाने पर नए पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के शामिल होने से बल की क्षमता में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के आवास, थानों के बुनियादी ढांचे और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार के लिए बजट में भारी बढ़ोतरी की गई। आधुनिक युग के अपराधों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को अत्याधुनिक





तकनीकों से लैस किया गया है। आपातकालीन सेवाओं के प्रतिक्रिया समय (Response Time) को न्यूनतम किया गया है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना मिलते ही पुलिस चंद मिनटों में मौके पर पहुंच जाती है। बढ़ते डिजिटल अपराधों को देखते हुए राज्य के सभी जनपदों और संभागों में आधुनिक साइबर थानों की स्थापना की गई है। 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के माध्यम से लाखों जन–सहयोग और सरकारी कैमरों को आपस में जोड़कर अपराधियों की निगरानी और घटनाओं के खुलासे को बेहद सटीक बनाया गया है।

सुदृढ़ कानून–व्यवस्था का सीधा प्रभाव उत्तर प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य पर दिखाई दे रहा है। भयमुक्त वातावरण ने राज्य को निवेश के सबसे पसंदीदा केंद्र (Investment Hub) के रूप में स्थापित कर दिया है। कानून के राज के कारण देश–विदेश के बड़े औद्योगिक घरानों ने उत्तर प्रदेश का रुख किया है। 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' के माध्यम से राज्य में लाखों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर रहे हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं।

अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम के पुनरुद्धार और प्रयागराज कुंभ जैसे भव्य आयोजनों के सुरक्षित प्रबंधन ने वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश की छवि को बदला है। आज रिकॉर्ड संख्या में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक बिना किसी सुरक्षा चिंता के राज्य का भ्रमण कर रहे हैं।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण तभी संभव हो सका, जब कार्यस्थलों पर सुरक्षा और पारदर्शिता का माहौल सुनिश्चित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृढ़ संकल्प और कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की कानून–व्यवस्था में आया बदलाव देश के प्रशासनिक इतिहास में एक मिसाल बन चुका है। अपराधियों के प्रति कठोरता और आम नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता की नीति ने राज्य को 'बीमारू राज्य' की श्रेणी से बाहर निकालकर 'उत्तम प्रदेश' के मार्ग पर अग्रसर कर दिया है।

आज उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो, किसान हो या युवा, स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। सुदृढ़ कानून–व्यवस्था के इस सुदृढ़ धरातल पर खड़ा उत्तर प्रदेश न केवल अपनी कानून–व्यवस्था के लिए सराहा जा रहा है, बल्कि विकास की नई ऊंचाइयों को छूते हुए भारत की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है। सुशासन का यह सफर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, समृद्ध और गौरवशाली भविष्य की नींव रख चुका है। ◆

(लेखक मुख्यमंत्री सूचना परिसर में फीचर लेखक हैं)

मो. : 6306959511

वृद्धाओं का सम्मान, सफर आसान

—कीर्ति श्रीवास्तव



वरिष्ठ महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि उन्हें अधिक स्वतंत्र, गतिशील और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदनशील पहल है

किसी भी समाज की प्रगति का वास्तविक मूल्यांकन इस बात से किया जा सकता है कि वह अपनी माताओं, बहनों और बेटियों के प्रति कितना संवेदनशील है। महिला सशक्तीकरण का अर्थ केवल महिलाओं को शिक्षा, रोजगार अथवा आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना नहीं है, इसका व्यापक अर्थ यह भी है कि प्रत्येक महिला को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ उपलब्ध हों। विशेष रूप से जीवन के उस पड़ाव पर, जब आय के साधन सीमित होने लगते हैं और स्वास्थ्य तथा सामाजिक आवश्यकताएँ बढ़ जाती हैं, सार्वजनिक सुविधाओं तक सुगम पहुँच महिला के आत्मविश्वास और जीवन–गुणवत्ता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

इसी व्यापक सोच को प्रतिबिंबित करती है उत्तर प्रदेश सरकार की 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना'। 25 अगस्त, 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई और 26 अगस्त, 2026 को लखनऊ में मुख्यमंत्री द्वारा इसका शुभारम्भ किया गया। योजना के अंतर्गत 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की साधारण बसों में आजीवन निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है।

यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वरिष्ठ महिलाओं की किसी एक समस्या का समाधान करने के बजाय उनके जीवन के कई पक्षों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आवागमन का खर्च कम होने से वे अपने आवश्यक कार्यों, स्वास्थ्य संबंधी यात्राओं, सामाजिक दायित्वों और पारिवारिक संबंधों के निर्वहन के लिए अधिक स्वतंत्रता के साथ यात्रा कर सकती हैं। इस दृष्टि से यह योजना सामाजिक कल्याण के साथ–साथ महिला सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में भी एक उल्लेखनीय पहल है।

वरिष्ठ मातृशक्ति को समर्पित एक संवेदनशील पहल

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविधतापूर्ण राज्य में सार्वजनिक परिवहन का महत्व अत्यधिक है। विशेषकर ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में अनेक महिलाओं के लिए जिला मुख्यालय, तहसील, चिकित्सालय, बैंक, बाजार या अन्य आवश्यक संस्थानों तक पहुँचने का प्रमुख माध्यम बस परिवहन ही है।

ऐसी स्थिति में वरिष्ठ महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा का महत्व केवल किराये की बचत तक सीमित नहीं है। एक महिला को यदि अपने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पताल जाना हो, किसी प्रशासनिक अथवा बैंकिंग कार्य के लिए तहसील या जिला मुख्यालय जाना हो, अपने मायके या अन्य रिश्तेदारों से मिलने जाना हो अथवा किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करनी हो, तो यात्रा पर होने वाला खर्च कई बार अनावश्यक आर्थिक बाधा बन जाता है।

सरकार की यह पहल उस बाधा को कम करती है। इससे वरिष्ठ महिलाओं को प्रत्येक यात्रा के लिए परिवार के अन्य सदस्यों पर आर्थिक रूप से निर्भर रहने की आवश्यकता भी कम हो सकती है। यही कारण है कि इस योजना को 'सुविधा से स्वाभिमान' की ओर बढ़ता कदम कहा जा सकता है।

आजीवन सुविधा, केवल अवसर विशेष की रियायत नहीं

उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन जैसे अवसरों पर महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा की व्यवस्था पहले भी की जाती रही है। अगस्त 2026 में भी रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों को एक सहयात्री सहित निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान की गई। यह सुविधा 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक रही।

लेकिन लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का स्वरूप इससे कहीं व्यापक है। यह किसी पर्व अथवा विशेष अवसर तक सीमित नहीं है, बल्कि 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए आजीवन सुविधा के रूप में लागू की गई है। 28 अगस्त, 2026 से पात्र महिलाएँ UPSRTC की साधारण बसों में इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं।

इस स्थायित्व में ही योजना की विशेष शक्ति निहित है। किसी विशेष दिवस पर मिलने वाली सुविधा निश्चित रूप से उपयोगी होती है, किंतु स्थायी सुविधा नागरिक को अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती है।

स्मार्ट कार्ड और सरल पहचान व्यवस्था

योजना के क्रियान्वयन में तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है। पात्र महिलाओं के लिए विशेष स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। यात्रा के दौरान पात्रता के सत्यापन के लिए आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र का उपयोग किया जा सकता है। स्मार्ट कार्ड जैसी व्यवस्था का लाभ यह हो सकता है कि योजना के संचालन में पारदर्शिता और प्रशासनिक सुविधा बढ़े। साथ ही, वरिष्ठ महिलाओं के लिए प्रक्रिया को सरल बनाए रखना आवश्यक है, ताकि तकनीकी व्यवस्था स्वयं किसी प्रकार की बाधा न बन जाए।

यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के लिए अगली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा की जाए और पात्र महिलाओं को आवेदन,



योजना के क्रियान्वयन में तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है। पात्र महिलाओं के लिए विशेष स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। यात्रा के दौरान पात्रता के सत्यापन के लिए आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र का उपयोग किया जा सकता है। स्मार्ट कार्ड जैसी व्यवस्था का लाभ यह हो सकता है कि योजना के संचालन में पारदर्शिता और प्रशासनिक सुविधा बढ़े। साथ ही, वरिष्ठ महिलाओं के लिए प्रक्रिया को सरल बनाए रखना आवश्यक है, ताकि तकनीकी व्यवस्था स्वयं किसी प्रकार की बाधा न बन जाए।



पहचान तथा यात्रा की प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो।

स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सहायक

वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक समय पर पहुँच अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली किसी वरिष्ठ महिला को चिकित्सकीय परामर्श, नियमित जांच अथवा उपचार के लिए अक्सर निकटतम कस्बे या जिला मुख्यालय तक जाना पड़ सकता है।

ऐसे में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। यह योजना स्वयं स्वास्थ्य योजना नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से उत्पन्न बेहतर गतिशीलता स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोगी भूमिका निभा सकती है।

इसी प्रकार, सामाजिक संपर्क भी वरिष्ठ नागरिकों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिश्तेदारों से मिलना, पारिवारिक कार्यक्रमों में भाग लेना अथवा धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होना उनके सामाजिक जीवन को सक्रिय बनाए रखने में सहायक होता है। यात्रा खर्च में कमी ऐसे अवसरों को अधिक सुलभ बना सकती है।

अहिल्याबाई होल्कर : नाम में निहित प्रेरणा

योजना का नामकरण लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर किया जाना भी सार्थक है। अहिल्याबाई होल्कर भारतीय इतिहास में सुशासन, लोककल्याण, न्यायप्रियता और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए स्मरण की जाती हैं। उनके नाम से जुड़ी योजना वरिष्ठ महिलाओं के सम्मान और सुविधा को समर्पित है—यह अपने आप में एक प्रेरक संदेश है। यह नामकरण उस विचार को आगे बढ़ाता है कि महिला नेतृत्व और महिला सम्मान भारतीय सामाजिक परंपरा के अभिन्न अंग रहे हैं। आधुनिक कल्याणकारी राज्य में इसी विचार को नई नीतियों और सार्वजनिक सुविधाओं के माध्यम से व्यवहार में उतारा जा सकता है।

आर्थिक सहायता से आगे बढ़कर आत्मविश्वास

महिला सशक्तीकरण के विमर्श में प्रायः रोजगार, आय और वित्तीय सहायता को प्रमुखता दी जाती है। निस्संदेह ये

अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सशक्तीकरण का एक और आधार है—गतिशीलता की स्वतंत्रता।

जो महिला बिना अनावश्यक आर्थिक चिंता के अपने आवश्यक कार्यों के लिए यात्रा कर सकती है, वह सार्वजनिक संस्थाओं तक अधिक आसानी से पहुँच सकती है। वह अपने सामाजिक संबंध बनाए रख सकती है और अपने व्यक्तिगत निर्णयों को अधिक स्वतंत्रता के साथ लागू कर सकती है। वरिष्ठ महिलाओं के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जीवन भर परिवार और समाज के लिए योगदान देने वाली माताओं को वृद्धावस्था में सम्मान, सुविधा और आत्मनिर्भरता का अनुभव कराना एक संवेदनशील सरकार की जिम्मेदारी भी है और सामाजिक दायित्व भी।

इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय सराहनीय है कि उसने वरिष्ठ महिलाओं के लिए परिवहन सुविधा को केवल प्रतीकात्मक कार्यक्रम न रखकर आजीवन सार्वजनिक सुविधा का स्वरूप दिया।

निष्कर्ष : मातृशक्ति के सम्मान का व्यावहारिक रूप

लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना को केवल निःशुल्क बस यात्रा की योजना कहना इसके व्यापक उद्देश्य को सीमित कर देना होगा। यह योजना वरिष्ठ महिलाओं के लिए आर्थिक राहत, गतिशीलता, सामाजिक सहभागिता और आत्मसम्मान के अनेक द्वार खोलने की क्षमता रखती है।

60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में आजीवन निःशुल्क यात्रा की सुविधा देना उत्तर प्रदेश सरकार की उस सोच को रेखांकित करता है जिसमें महिला कल्याण को केवल सहायता प्रदान करने के बजाय उनके जीवन को अधिक सुगम और सम्मानजनक बनाने से जोड़ा गया है।

वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखें तो महिला एवं बाल विकास के लिए बढ़ा हुआ बजटीय प्रावधान, निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मिशन शक्ति जैसे प्रयास यह संकेत देते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तीकरण को बहुआयामी रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना इसी सतत प्रयास की एक नई और सराहनीय कड़ी है। यह उस भावना को व्यवहार में उतारती है कि जिन माताओं ने परिवार और समाज के निर्माण में अपना जीवन समर्पित किया, उनके जीवन के इस चरण में सरकार उनके साथ खड़ी हो और उनकी यात्रा को आर्थिक चिंता से मुक्त करे।

वास्तव में, किसी वरिष्ठ महिला के लिए निःशुल्क बस यात्रा केवल एक टिकट का मूल्य समाप्त नहीं करती—वह कई बार निर्भरता की एक बाधा को समाप्त करती है और स्वतंत्रता की एक नई राह खोलती है। यही इस योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि और महिला सशक्तीकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की सार्थक अभिव्यक्ति है। ◆

(लेखिका नेशनल पी.जी. कॉलेज में असि. प्रोफेसर हैं)
मो. : 7706968376



अटल आवासीय विद्यालय : वंचित बच्चों के सपनों को नई उड़ान

—सलोनी कसेरे

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के साथ–साथ अपनी विविधता, संस्कृति, परंपरा और प्रतिभा के लिए भी जाना जाता है। प्रदेश के गाँवों, कस्बों और शहरों में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं, जिनमें प्रतिभा और आगे बढ़ने की पूरी क्षमता है, लेकिन आर्थिक परिस्थितियाँ कई बार उनके सपनों के रास्ते में बाधा बन जाती हैं। ऐसे बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हैं। इन विद्यालयों का उद्देश्य केवल बच्चों को शिक्षा देना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित वातावरण, अनुशासन, संस्कार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध कराना है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई यह पहल विशेष रूप से श्रमिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके माता–पिता दिन–रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन–पोषण करते हैं। ऐसे परिवारों के बच्चों में पढ़ने और आगे बढ़ने की इच्छा तो होती है, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसी बच्चे की पढ़ाई केवल इसलिए रुक जाए कि उसके माता–पिता के पास पर्याप्त आर्थिक साधन नहीं हैं, यह किसी भी समाज के लिए चिंता का विषय है। अटल आवासीय विद्यालय इसी चुनौती का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास हैं।

शिक्षा के साथ आवासीय सुविधा

अटल आवासीय विद्यालयों की सबसे बड़ी विशेषता इनका आवासीय स्वरूप है। यहाँ विद्यार्थियों को विद्यालय परिसर में रहकर पढ़ाई करने का अवसर मिलता है। इससे उन बच्चों को विशेष लाभ मिलता है, जो दूर–दराज के



ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और जिनके लिए प्रतिदिन विद्यालय आना–जाना आसान नहीं होता।

आवासीय व्यवस्था के कारण बच्चों को पढ़ाई के लिए एक नियमित और अनुशासित वातावरण मिलता है। उनका समय पढ़ाई, खेल, योग, सांस्कृतिक गतिविधियों और अन्य रचनात्मक कार्यों में व्यवस्थित तरीके से लगाया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों में समय का सदुपयोग करने, अनुशासन में रहने और अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहने की आदत विकसित होती है।

यह व्यवस्था उन अभिभावकों के लिए भी राहत का माध्यम बनती है, जो आर्थिक कठिनाइयों के बीच अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। उन्हें यह भरोसा मिलता है कि उनके बच्चों को शिक्षा के साथ रहने और दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ी सुविधाएं भी एक व्यवस्थित वातावरण में प्राप्त होंगी।

आज दुनिया तेजी से बदल रही है। तकनीक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी डिजिटल माध्यमों, कंप्यूटर, इंटरनेट और आधुनिक शिक्षण तकनीकों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। इसलिए अटल आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना भी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को यदि प्रारंभ से ही आधुनिक शैक्षिक संसाधनों का अनुभव मिलता है, तो वे भविष्य की प्रतिस्पर्धा में बेहतर ढंग से भाग ले सकते हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच

उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को विकास की आधारशिला माना गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। अटल आवासीय विद्यालय भी इसी व्यापक सोच का हिस्सा हैं, जिसमें समाज के उन वर्गों के बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

योगी आदित्यनाथ जी का मानना रहा है कि प्रदेश का विकास तभी व्यापक और स्थायी हो सकता है, जब बच्चों और युवाओं को बेहतर शिक्षा और अवसर उपलब्ध हों। आज का विद्यार्थी ही कल का शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रशासनिक अधिकारी, उद्यमी, खिलाड़ी और जनसेवक बनेगा। इसलिए बच्चों में निवेश वास्तव में प्रदेश के भविष्य में निवेश है।

अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से सरकार का प्रयास है कि श्रमिक परिवारों के बच्चों को भी ऐसा शैक्षिक वातावरण मिले, जहाँ वे अपनी प्रतिभा को पहचान सकें और उसे आगे बढ़ा सकें।

गरीब परिवारों के बच्चों के लिए बड़ा अवसर

हमारे समाज में अक्सर आर्थिक स्थिति और शिक्षा के बीच गहरा संबंध दिखाई देता है। संपन्न परिवार अपने बच्चों को बेहतर विद्यालय, कोचिंग, पुस्तकें, डिजिटल संसाधन और अन्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरी ओर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है।

ऐसे में अटल आवासीय विद्यालयों की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ उद्देश्य यह है कि बच्चे की शिक्षा उसके माता–पिता की आर्थिक स्थिति पर निर्भर न रहे। यदि किसी बच्चे में प्रतिभा और मेहनत करने की क्षमता है, तो उसे आगे बढ़ने के लिए अवसर मिलना चाहिए।

किसी मजदूर का बेटा या बेटी यदि भविष्य में डॉक्टर बनने का सपना देखता है, किसी किसान का बच्चा वैज्ञानिक बनना चाहता है या किसी सामान्य परिवार का विद्यार्थी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, तो उसे अपने सपनों की ओर बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसे सपनों को मजबूत आधार देने में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

केवल पढ़ाई नहीं, व्यक्तित्व निर्माण भी

विद्यालय का उद्देश्य केवल किताबें पढ़ाना नहीं होता। वास्तविक शिक्षा वह है, जो विद्यार्थी के व्यक्तित्व का निर्माण करे। अटल आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में शिक्षा के साथ खेल, योग, सांस्कृतिक



गतिविधियों और अनुशासन को महत्व दिया जाना इस दृष्टि से उपयोगी है।

खेल बच्चों में टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करते हैं। योग उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित रहने में सहायता करता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों को अपनी परंपरा और संस्कृति से जोड़ते हैं। वहीं नियमित अध्ययन उन्हें ज्ञान और तर्क की दुनिया से परिचित कराता है।

जब ये सभी चीजें एक साथ मिलती हैं, तो विद्यार्थी केवल परीक्षा पास करने वाला छात्र नहीं रहता, बल्कि वह एक जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ता है।

आधुनिक शिक्षा की ओर कदम

आज दुनिया तेजी से बदल रही है। तकनीक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी डिजिटल माध्यमों, कंप्यूटर, इंटरनेट और आधुनिक शिक्षण तकनीकों का महत्व लगातार बढ़ रहा है।

इसलिए अटल आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना भी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को यदि प्रारंभ से ही आधुनिक शैक्षिक संसाधनों का अनुभव मिलता है, तो वे भविष्य की प्रतिस्पर्धा में बेहतर ढंग से भाग ले सकते हैं।

आज का बच्चा केवल अपने शहर या प्रदेश से नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। ऐसे में उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ तकनीकी ज्ञान, भाषा कौशल, तार्किक सोच और रचनात्मक क्षमता विकसित करने के अवसर मिलना जरूरी है।

अनुशासन और संस्कार

आवासीय विद्यालयों में बच्चों को अनुशासन का महत्व भी समझाया जा सकता है। समय पर उठना, पढ़ाई करना, खेलना, भोजन करना और निर्धारित दिनचर्या का पालन करना बच्चों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है।

शिक्षा के साथ संस्कार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

अपने माता–पिता का सम्मान करना, शिक्षकों का आदर करना, सहपाठियों के साथ सहयोग करना, पर्यावरण की रक्षा करना और समाज के प्रति जिम्मेदार होना अच्छे नागरिक की पहचान है।

यदि विद्यार्थी ज्ञान के साथ अच्छे संस्कार लेकर विद्यालय से निकलता है, तो वह अपने परिवार और समाज के लिए भी सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनता है।

बेटियों के लिए भी अवसर

समाज के विकास में बेटियों की शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब एक बेटी शिक्षित होती है तो उसका लाभ केवल उसके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचता है।

आवासीय शिक्षा की व्यवस्था उन परिवारों की बेटियों के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर सकती है, जहाँ दूर विद्यालय होने या अन्य सामाजिक–आर्थिक कारणों से पढ़ाई जारी रखना कठिन होता है। सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर बेटियाँ अपने सपनों को नई दिशा दे सकती हैं।

एक शिक्षित बेटी अपने अधिकारों को समझती है, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करती है और समाज में सकारात्मक भूमिका निभाती है।

गाँव और गरीब परिवारों से निकलेंगे भविष्य के सितारे

उत्तर प्रदेश के गाँवों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता केवल उस प्रतिभा को सही मंच देने की है। हो सकता है कि किसी छोटे से गाँव में रहने वाला बच्चा भविष्य का बड़ा वैज्ञानिक हो। किसी श्रमिक परिवार की बेटी देश की उत्कृष्ट खिलाड़ी बन सकती है। कोई सामान्य परिवार का विद्यार्थी प्रशासनिक सेवा में जाकर समाज की सेवा कर सकता है।

अटल आवासीय विद्यालयों का सबसे बड़ा महत्व इसी संभावना में छिपा है। ये विद्यालय बच्चों को केवल वर्तमान की परिस्थितियों से बाहर निकालने का प्रयास नहीं करते,





बल्कि उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने का अवसर प्रदान करते हैं।

प्रदेश के भविष्य की मजबूत नींव

किसी भी राज्य की असली ताकत उसकी सड़कें, इमारतें और उद्योग ही नहीं होते, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत वहाँ के शिक्षित, कुशल और संस्कारी नागरिक होते हैं। आज जिन बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, वही आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, प्रशासन, विज्ञान, खेल, उद्योग और सामाजिक विकास में योगदान देंगे।

इसलिए अटल आवासीय विद्यालयों को केवल शिक्षा योजना के रूप में देखने के बजाय मानव संसाधन के निर्माण की पहल के रूप में देखना चाहिए। यदि इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता लगातार बेहतर होती रहे, शिक्षकों को आवश्यक संसाधन मिलते रहें, विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक और खेल की सुविधाएँ मिलें तथा उनके व्यक्तित्व विकास पर निरंतर ध्यान दिया जाए, तो आने वाले वर्षों में इनका प्रभाव और व्यापक हो सकता है।

निष्कर्ष

अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश में उन बच्चों के लिए आशा, अवसर और आत्मविश्वास का माध्यम बन सकते हैं, जिनके सपने आर्थिक परिस्थितियों के कारण सीमित हो जाते हैं। इन विद्यालयों का उद्देश्य यह संदेश देना है कि प्रतिभा किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं है। प्रतिभा गाँव में भी है, श्रमिक परिवारों में भी है और सामान्य परिवारों में भी है। जरूरत है तो केवल उसे अवसर देने की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के बीच अटल आवासीय विद्यालय एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आए हैं। इनका वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होगा कि आने वाले वर्षों में यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी अपने जीवन में कितनी ऊँचाइयाँ प्राप्त करते हैं और समाज के विकास में कितना योगदान देते हैं।

अटल आवासीय विद्यालय केवल ईंट–पत्थर से बने भवन नहीं हैं। ये उन सपनों के घर हैं, जिन्हें आर्थिक परिस्थितियाँ कभी दबा देती थीं। यहाँ किताबों के साथ उम्मीदें पढ़ाई जाती हैं, अनुशासन के साथ आत्मविश्वास सिखाया जाता है और शिक्षा के साथ भविष्य की राह तैयार की जाती है।

यदि एक बच्चे के हाथ में किताब आ जाए, उसकी आँखों में सपना आ जाए और उसे उस सपने को पूरा करने का अवसर मिल जाए, तो यही किसी भी कल्याणकारी व्यवस्था की सबसे बड़ी सफलता है। अटल आवासीय विद्यालय–शिक्षा से सशक्तीकरण, अवसर से आत्मविश्वास और सपनों से उज्ज्वल भविष्य की ओर उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण कदम। ◆

(लेखिका पीएमश्री कम्पोजिट स्कूल में अनुदेशक हैं)
मो. : 7300560056

उन्नत किसान, समृद्ध प्रदेश

नया भारत, नया उत्तर प्रदेश



खेती-बाड़ी में ड्रोन का उपयोग

ड्रोन हेतु 50% तक अनुदान



विकास की गति अपार, डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

पहले था अनादर
आज अवसर बराबर

अपना यूपी बदल गया





2017-18 में
महिला श्रम बल
भागीदारी 13 प्रतिशत

आज महिला श्रम
बल भागीदारी
36 प्रतिशत

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. स्वत्वाधिकारी के लिए विशाल सिंह, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ द्वारा प्रकाशित तथा प्रकाश एन. भार्गव, प्रकाश पैकेजर्स, लखनऊ द्वारा मुद्रित, सम्पादक—चन्द्र विजय वर्मा।